



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229615  
CG-DL-E-15092021-229615

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2021/भाद्र 23, 1943

No. 265]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021/BHADRA 23, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्या: एडी (ओआई) - 29/2020)

**विषय:** चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम हाइड्रोसल्फाइड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

**फा. सं. 6/35/2020-डीजीटीआर.— क. मामले की पृष्ठभूमि**

समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (जिसे आगे यहां "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए

समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार ट्रांसपेक-सिलोक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे यहां "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत दस्तावेजयुक्त याचिका और प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के किसी प्रकार के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्ति करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 16 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/35/2020-डीजीटीआर जारी की।

## ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
  - क. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की कार्रवाई से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
  - ख. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 16 सितंबर, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
  - ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 16 सितंबर, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना दें और नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने ज्ञात विचार दें।
  - घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध करायी।
  - ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भी भेजी गई थी।
  - च. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी जांच की शुरुआत की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार अपने अनुरोध देने का अवसर दिया:
    - (i) जिन्हे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड फैक्टरी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
    - (ii) ग्वांगडोंग झोंगचेंग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
    - (iii) हैनान झोंगक्सिन केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
    - (iv) जिन्हे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड फैक्टरी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
    - (v) सीएनएसजी अनहुई होंग सिफांग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
    - (vi) झेजियांग हुइडेलोंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
    - (vii) झेजियांग रूटू कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
    - (viii) अनहुई चोलोरो अल्कली केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

- (ix) आन्यांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
  - (x) हंसोल केमिकल, कोरिया गणराज्य
  - (xi) पूहंग फोटो-केमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
- छ. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी।
- (i) मोरारजी ब्रेम्बाना
  - (ii) मॉडर्न डेनिम
  - (iii) मदुरा कोट्स लिमिटेड
  - (iv) ईआईसीएल लिमिटेड
  - (v) रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - (vi) वेलस्पन टेरी तौलिए
  - (vii) आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स लिमिटेड
  - (viii) एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
  - (ix) वर्धमान फैब्रिक्स
  - (x) आर्किड फार्मा
- झ. प्राधिकारी ने निम्नलिखित एसोसिएशनों को भी अधिसूचना भेजी जिसमें उनसे कहा गया था कि वे जांच की शुरुआत के संबंध में अपने सभी सदस्यों को सूचित करें और यदि कोई प्रत्युत्तर टिप्पणियां हैं तो प्रस्तुत करें।
- (i) इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन
  - (ii) टेक्सटाइल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
  - (iii) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन
  - (iv) गुजरात डाईस्टफ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन
  - (v) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
  - (vi) कांफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
  - (vii) एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
- ञ. संबद्ध सामान के किसी भी आयातक और प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक आयातक के रूप में जांच प्रक्रिया के दौरान अनुरोध दायर किए हैं।
- ट. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण की अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि शामिल है।
- ठ. जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देन वार आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ड. आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- ढ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि

वे अन्य सभी हितवद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चल रही वैश्विक महामारी के कारण वास्तविक रूप से पहुंच में नहीं थी।

- ण. घरेलू उद्योग ने अपने सनदी/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार और सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं विक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है। यह क्षति रहित कीमत यह सुनिश्चित करने के लिए मानी गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 21 जून, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितवद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।
- थ. जांच प्रक्रिया के दौरान, हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, दिए गए तर्कों और विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- द. प्राधिकारी ने यथासंभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन कर जांच प्रक्रिया के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट किया, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है।
- ध. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- न. जहां कहीं किसी हितवद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया है।
- प. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितवद्ध पक्षकारों को दिनांक 9 सितंबर, 2021 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उस पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई प्राप्त टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- फ. इन अंतिम जांच परिणामों में \*\*\* गोपनीय आधार पर किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- व. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

#### ग. **विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और समान वस्तु**

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"सोडियम हाइड्रोसल्फाइड", चाहे जिंक का प्रयोग करके या सोडियम फॉर्मेट का उपयोग करके उत्पादित किया गया हो, जिसे "हाइड्रोसल्फाइड कॉन्सेंट्रेट" या "सोडियम डाइथियोनाइट" या "सोडियम हाइड्रोसल्फाइड" या "एसएचएस" के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सफेद या भूरे रंग का सफेद पाउडर है, जो तीखी गंध के साथ दिखाई देने वाले बाह्य कणों से मुक्त होता है। इसका क्रिस्टलीय रासायनिक सूत्र  $Na_2S_2O_4$  है। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे वस्त्र, साबुन, गुड़, गोंद और कम करने वाले एजेंट में किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क शीर्ष 28311010 और 28321020 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

## ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद से भिन्न हैं, जैसा कि आवेदक ने अपनी वेबसाइट पर स्वीकार किया है लेकिन याचिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
- (ii) जस्ता प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद मांग, उपयोग, उत्पादन प्रक्रिया, लागत और बिक्री मूल्य के संदर्भ में सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित उत्पादों से भिन्न होते हैं। जस्ता प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन व्यापार में महंगा और असामान्य है जबकि फॉर्मेट प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन अधिक सामान्य है, जिसका उपयोग चीन जन. गण. में किया जाता है।
- (iii) आवेदक की वेबसाइट के अनुसार जिंक और सोडियम फॉर्मेट प्रक्रियाओं के माध्यम से विनिर्मित उत्पादों का घनत्व अलग-अलग होता है, लेकिन याचिका में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।
- (iv) फ्री-फ्लोइंग मशीनों के कारण, चीन जन. गण. केवल एसएफ मार्ग के माध्यम से एसएचएस का उत्पादन करता है और इसके अतिरिक्त, चीनी सरकार ने 3 वर्ष पूर्व जस्ता विनिर्माण इकाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रकार, एसएचएस (जेडएन) का बिल्कुल भी आयात नहीं है।
- (v) घरेलू उद्योग ने कोरिया गणराज्य में उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त उत्पादन मार्ग को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- (vi) टीसीपी इंडिया सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण करती है और अपनी वेबसाइट पर उसने स्वीकार किया है कि ऐसे उत्पादों को जस्ता या अमलगम प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित उत्पादों पर लाभ है क्योंकि उनमें जस्ता, लोहा या पारा के निशान भी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग अपनी याचिका में अमलगम प्रक्रिया का विवरण प्रदान करने में विफल रहा है।
- (vii) विचाराधीन उत्पाद की कीमत, मांग और उपयोग पैकिंग के आधार पर भिन्न-भिन्न है। चीन जन. गण. से निर्यात 50 किलोग्राम पैकिंग में पेश किया जाता है जो व्यापार में महंगा और अधिक सामान्य है जबकि घरेलू उद्योग 1 किलोग्राम से 100 किलोग्राम पैकिंग के साथ-साथ हल्के स्टील ड्रम और एचएमएचडीपीई कार्बो में बड़े आकार की पैकिंग प्रदान करता है। निर्यात के लिए, घरेलू उद्योग पैलेट के साथ और बिना पैलेट के स्टील ड्रम में दो पैकिंग, 50 किग्रा और 100 किग्रा. पेश करता है।
- (viii) उत्पादों की कीमत और उपयोग भी पाउंडर के रूप में या गांठ के रूप में भिन्न होता है, जिसका प्रकटन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है।
- (ix) कोरिया गणराज्य से आयातित उत्पाद का परख मूल्य केवल न्यूनतम 90% है और चीन जन. गण. से आयातित उत्पाद का न्यूनतम 85-88% है, जिसमें 88% शुद्धता व्यापार में सबसे आम है। विचाराधीन उत्पाद की कीमत, मांग, आपूर्ति और उपयोग शुद्धता के अनुसार अलग-अलग होती है और जैसे-जैसे शुद्धता बढ़ती है, कीमत भी बढ़ती जाती है।
- (x) घरेलू उद्योग ने इस बारे में सूचना नहीं दी है कि क्या वे 85%, 90% और ग्रेड ई के परख स्तर के साथ उत्पाद का उत्पादन करते हैं, जो कि संबद्ध आयात हैं और क्या उनके उत्पाद एवं आयातों के बीच कोई अंतर है।
- (xi) घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में यह प्रकट नहीं किया है कि थियोरिया डाइऑक्साइड विचाराधीन उत्पाद का प्रतिस्थापन है।
- (xii) घरेलू उद्योग ने हाइड्रोस डी और ल्यूकोसेफ डी7 के बीच अंतर का प्रकटन नहीं किया है।
- (xiii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में बीआईएस प्रमाणपत्र नहीं है।

## ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (एसएचएस) है, चाहे वह जिंक या सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित किया गया हो। इसे हाइड्रोसल्फाइड कॉन्सेंट्रेट या सोडियम डाइथियोनाइट या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ) के रूप में भी जाना जाता है और सीमा शुल्क कोड 28311010 और 28321020 के तहत वर्गीकरणीय है।
- (ii) चीन और भारत में जस्ता मार्ग और सोडियम फॉर्मेट मार्ग दोनों का उपयोग करके सामान का उत्पादन किया जाता है और दोनों उत्पादों का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है जो जस्ता मार्ग के माध्यम से उत्पादित उत्पाद के लिए कीमत, थोड़ा अधिक होने के नाते, के बावजूद विभिन्न रूपों में विभिन्न मार्गों के माध्यम विनिर्मित उत्पाद नहीं मानते।
- (iii) चूंकि उत्पाद उपभोक्ताओं की लागत का एक प्रमुख भाग नहीं है, अतः उपभोक्ता किसी विशेष उत्पाद की कीमत के बजाय सुविधा और अन्य कारकों को प्राथमिकता देते हैं।
- (iv) जिंक प्रक्रिया और सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया का उपयोग करने वाले उत्पादों को कई अनुप्रयोगों में परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है जबकि डेनिम (वस्त्र) और गुड़ उद्योग में प्रयोक्ता कम धूल, बेहतर स्थिरता आदि जैसे गुणधर्मों के कारण जस्ता मार्ग का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ऐसे उपभोक्ता सीमित होते हैं और अधिकतर उपभोक्ता उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग करते हैं।
- (v) आयात आंकड़ों विवरण के आधार पर सोडियम फॉर्मेट रूट या जिंक रूट के माध्यम से उत्पादित सामान के पृथक्करण की अनुमति नहीं देते हैं।
- (vi) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों को पूर्व जांच में चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातित सामानों की समान वस्तु माना गया था।
- (vii) चीन जन. गण. में उत्पादक दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग करके इस उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं।
- (viii) यहां तक कि यद्यपि डेनिम वस्त्र उद्योग जिंक मार्ग का उपयोग करके उत्पादित सामानों को प्राथमिकता देता है, तथापि अन्य उपभोक्ता इस उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया के बजाय सस्ते उत्पाद पर ध्यान देते हैं। आयातित सामान और घरेलू उद्योग में जिंक मार्ग का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद शामिल हैं।
- (ix) घरेलू उद्योग जिंक और सोडियम फॉर्मेट रूट से संबद्ध सामानों का उत्पादन करता है, जो कि रासायनिक संरचना में काफी सीमा तक समान हैं और परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किये जाते हैं। चूंकि टीसीपी इंडिया घरेलू उद्योग का भाग नहीं है, अतः इसके द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया असंगत है।
- (x) हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के विपरीत, आवेदक द्वारा अपनी वेबसाइट में कोई दावा नहीं किया गया है कि जिंक और सोडियम फॉर्मेट के माध्यम से विनिर्मित उत्पादों के घनत्व में अंतर है।
- (xi) घरेलू उद्योग की उत्पादन का मार्ग विनिर्दिष्ट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि इसे आयात आंकड़ों से पहचाना नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयातक ने उत्पादन प्रक्रिया में संभावित अंतरों के प्रभाव को न तो परिमाणित किया है और न ही सिद्ध किया है।
- (xii) घरेलू उद्योग 88% और 84% के परख स्तर के साथ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है, जबकि अन्य घरेलू उत्पादक 70-92% के बीच सामान का उत्पादन करते हैं।
- (xiii) यद्यपि गुलशन केमिकल्स द्वारा उत्पादित सामानों की शुद्धता असंगत है, तथापि यह संबद्ध सामानों का उत्पादन 85%, सामान्य रूप से 88% और मांग पर 90% के परख स्तर के साथ करती है।
- (xiv) आवेदक ने संबद्ध सामान की आपूर्ति केवल 50 किग्रा पैकेजिंग में की है क्योंकि ग्राहक की प्राथमिकता के आधार पर 100 किग्रा पैकेजिंग को बंद कर दिया गया था।
- (xv) उत्पाद की कीमत और शुद्धता के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि कम शुद्धता वाले दोनों उत्पाद अधिक कीमत पर बेचे जाते हैं।
- (xvi) अमलगम प्रक्रिया का उपयोग केवल जर्मनी में संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए किया जाता है और भारत या संबद्ध देशों में व्यापक रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

- (xvii) आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद हाइड्रोस-डी एक विशेष उत्पाद है जो अतिरिक्त सुधारों के कारण डेनिम की इंडिगो डाइंग में बेहतर निष्पादन करता है। अधिक उन्नत होने के बावजूद, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में अनिवार्य रूप से आयातित सामानों के समान वही विशेषताएं और संरचना होती है। विचाराधीन उत्पाद और एक प्रकार के आधार पर समग्र रूप से घरेलू उत्पाद की तुलनीयता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
- (xviii) हाइड्रोस डी और ल्यूकोसेफ डी7 विचाराधीन उत्पाद की 2 विशेष किस्में हैं, जिनमें रासायनिक संरचना के मामले में कोई अंतर नहीं है, जबकि कीमत के मामले में, हाइड्रोस डी की कीमत अधिक है।
- (xix) सोडियम हाइड्रोसल्फाइड गांठ के रूप में उपलब्ध नहीं है और इसे केवल पाउडर के रूप में बेचा जाता है, क्योंकि उत्पादों की कीमत और उपयोग हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार स्वरूप में भिन्न नहीं होते हैं।
- (xx) ग्रेड ई उत्पाद बीएसएसएफ, जर्मनी का एक ब्रांड है और संबद्ध देशों से आयात नहीं किया जाता है।
- (xxi) इस दावे के संबंध में कि याचिका में उत्पाद के विकल्प का उल्लेख नहीं किया गया था, यह अनुरोध किया जाता है कि थियोरिया डाइऑक्साइड का उपयोग केवल सैद्धांतिक रूप से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के लिए प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से, कम निष्पादन के कारण इसका उपयोग भारत में किसी भी निचले स्तर के प्रयोक्ता द्वारा नहीं किया जाता है। किसी भी दशा में, संबद्ध सामान की मांग में काफी वृद्धि हुई है और क्षति तथाकथित समान विकल्प की कीमत के कारण नहीं हुई है।
- (xxii) हितवद्ध पक्षकारों के आरोपों के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद बीआईएस प्रमाणित है।
- (xxiii) इस तर्क के संबंध में कि सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट कच्ची सामग्री के रूप में प्रकट नहीं किए गए थे, यह अनुरोध किया जाता है कि ये विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री नहीं हैं बल्कि स्थिरीकारक तत्वों के रूप में जोड़े गए हैं और विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सोडियम हाइड्रोसल्फाइड" है, चाहे वह जिंक या सोडियम फॉर्मेट का उपयोग करके उत्पादित किया गया हो, जिसे "हाइड्रोसल्फाइड कॉन्सेंट्रेट" या "सोडियम डाइथियोनाइट" या "सोडियम हाइड्रोसल्फाइड" या "एसएसएस" के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सफेद या भूरे रंग का सफेद पाउडर है, जो तीखी गंध के साथ दिखाई देने वाले बाह्य कणों से मुक्त होता है। इसका क्रिस्टलीय रासायनिक सूत्र  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$  है।
- विचाराधीन उत्पाद या तो "जिंक प्रोसेस" या "सोडियम फॉर्मेट प्रोसेस" का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। जिंक प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जस्ता धूल की अभिक्रिया और परिणामी जस्ता नमक को कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की मौजूदगी में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड में परिवर्तित करना शामिल है। सोडियम फॉर्मेट प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उत्पादन करने के लिए मेथनॉल घोल में सोडियम फॉर्मेट के साथ कास्टिक सोडा और सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया शामिल है।
- विचाराधीन उत्पाद शीर्ष 2831 10 10 और 2832 10 20 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे वस्त्र, साबुन, शीरा, गोंद और कम करने वाले एजेंट, धातुओं से धातु आयनों का डाइसल्फाइड, ऊन के बालों में जुड़ाव आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में संबद्ध सामानों के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित सूची में दिए गए हैं:
  - टेक्सटाइल - वैंट की रंगाई और इंडिगो डाई के लिए और डाई की स्ट्रिपिंग के लिए सिंथेटिक वस्त्र को कम करने हेतु।
  - ब्लीचिंग ऐज - ग्राउंड वुड पल्प, साबुन, चीनी, शीरा, गोंद काओलिन (मिट्टी)।
  - रेज्यूसिंग एजेंट - धातु आयनों से धातुओं में कमी, वूल हेयर में डाइसल्फाइड लिंकेज, नाइट्रोजन कंपाउंड।
  - फार्मास्यूटिकल्स - रासायनिक अभिक्रिया, डी-कलरिंग अंतिम उत्पाद।
  - पॉलिमर - ऑक्सीजन स्केवेजिंग एजेंट।

11. इस दावे के संबंध में कि जस्ता प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित उत्पादों से भिन्न हैं, जिसका उपयोग चीन जन. गण. में उत्पादकों द्वारा किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग दोनों प्रक्रियाओं जिनका तथा सोडियम फॉर्मेट का उपयोग करके उत्पादों का उत्पादन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिए हैं कि संबंधित देशों में भी संबंधित सामानों का उत्पादन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग और चीन जन. गण. में उत्पादकों द्वारा लगाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, पूर्व जांचों में भी, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातित सामानों की समान वस्तु है।
12. इस दावे के संबंध में कि जिनक प्रक्रिया और सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि उत्पादों को विभिन्न मार्गों से उत्पादित किए जाने के बावजूद, दोनों उत्पादों का उपयोग अंतिम-प्रयोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि अधिकतर उपभोक्ता दोनों प्रक्रियाओं से उत्पादित सामानों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते हैं और केवल 5% उपभोक्ता ही जिनक मार्ग वाले उत्पाद का प्रयोग करते हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि ये उपभोक्ता जिनक रूट वाले उत्पाद का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अन्य उत्पाद का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल इसलिए कि उत्पाद की लागत इतनी काफी नहीं है और इन उपभोक्ताओं का मानना है कि जिनक मार्ग का उपयोग उनकी उत्पादन प्रक्रिया में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। शेष उपभोक्ता फॉर्मेट रूट उत्पाद का उपयोग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जिनक रूट उत्पाद से सस्ता है।
13. आयातक, संदीप ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने यह भी दावा किया है कि 85-88% की शुद्धता वाले उत्पाद को चीन जन. गण. से आयात किया जाता है, जबकि 90% परख मूल्य वाला उत्पाद कोरिया गणराज्य से आयात किया जाता है। आयातक ने दावा किया कि उत्पाद की शुद्धता ने उसकी कीमत, मांग, आपूर्ति और उपयोग को प्रभावित किया। प्रत्युत्तर में, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है कि उत्पाद की शुद्धता नीचे दिए गए अनुसार कीमत को प्रभावित नहीं कर रही है।

शुद्धता	चीन जन. गण. से आयात (मी. टन)	कीमत (रु./मी. टन)
85%	762	63,141
88%	4,328	61,607
90%	811	61,202

14. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिए हैं कि जहां उसने 88 प्रतिशत और 84 प्रतिशत के परख स्तर के साथ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है, वहीं समर्थकों ने 70-92% तक के परख स्तरों के साथ इस उत्पाद का उत्पादन किया है। आयातक ने यह नहीं दर्शाया है कि विभिन्न परख मूल्यों के उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं।
15. सामानों की पैकेजिंग के संबंध में, आयातक ने दावा किया है कि संबंधित देशों से आयातित सामान 50 किलोग्राम पैकिंग में पैक किया जाता है, जो कि महंगा है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि वह 50 किलोग्राम के पैक में संबंधित सामानों की आपूर्ति कर रहा है। अतः, सामानों की पैकेजिंग के आकार में कोई अंतर नहीं है।
16. थियोरिया डाइऑक्साइड के रूप में प्रतिस्थापन की उपलब्धता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की तुलना में इसके खराब निष्पादन के कारण भारत में किसी भी निचले स्तर प्रयोक्ता उद्योग द्वारा थियोरिया डाइऑक्साइड का उपयोग इसके प्रतिस्थापन के रूप में नहीं किया जाता है।
17. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग हाइड्रोस डी और ल्यूकोसेफ डी7 का उत्पादन कर रहा है, यह नोट किया जाता है कि ये विचाराधीन उत्पाद की केवल दो किसमें हैं और ये दोनों रासायनिक संरचना और विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं।
18. ग्रेड ई को अलग करने के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ग्रेड ई के लिए मांग मौजूद है और घरेलू उद्योग के पास इसका विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है।



19. विचाराधीन उत्पाद के स्वरूप के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में दी गई सूचना के अनुसार संबद्ध सामानों को केवल पाउडर के रूप में बेचा जाता है।
20. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि, आयातक के तर्क के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान वीआईएस प्रमाणित हैं। घरेलू उद्योग ने अपने वीआईएस प्रमाणपत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई है।
21. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और संबद्ध देशों से आयातित सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान आयातित सामानों के समान वस्तु हैं।

#### घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

##### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
  - (i) गुलशन केमिकल्स अपनी वेबसाइट के अनुसार 90% शुद्धता वाले संबद्ध सामानों का उत्पादन नहीं करता है।
  - (ii) कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने न तो अपनी वेबसाइट पर संबद्ध सामानों के उत्पादन का उल्लेख किया है और न ही उन्होंने जांच में भाग लिया है।
  - (iii) अन्य घरेलू उत्पादकों ने अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं और इस प्रकार केवल एक कंपनी के आंकड़ों पर आधारित जांच अनुचित है।

##### घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

23. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
  - (i) यह आवेदन पत्र ट्रांसपेक-सिलोक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो देश में संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका देश में कुल उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
  - (ii) आवेदक ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और भारत में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध नहीं है।
  - (iii) याचिका का डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, टीसीपी लिमिटेड और गुलशन केमिकल्स लिमिटेड द्वारा समर्थन किया गया है।
  - (iv) कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं लेकिन अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है।
  - (v) समर्थकों के साथ आवेदक पूरे भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - (vi) चूंकि कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है, अतः वे संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक नहीं हैं और इसलिए उन्होंने जांच में भाग नहीं लिया है।
  - (vii) आवेदक के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इसलिए यह घरेलू उद्योग है, जैसा कि जांच की शुरुआत के दौरान प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है। अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत न करने से वर्तमान जांच में आवेदक के अधिकारों का पूर्वाग्रह नहीं हो सकता।

##### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

25. यह आवेदन पत्र ट्रांसपेक-सिलोक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध नहीं है और न ही उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।
26. 3 अन्य उत्पादक हैं जो भारत में संबद्ध सामानों के विनिर्माण में लगे हुए हैं। संबद्ध सामानों के तीनों उत्पादकों ने वर्तमान आवेदन पत्र का समर्थन किया है, अर्थात्:

क. डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. टीसीपी लिमिटेड

ग. गुलशन केमिकल्स लिमिटेड

एक अन्य उत्पादक, कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

27. कुल घरेलू उत्पादन का निर्धारण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यौरों के आधार पर किया गया है। आवेदक उत्पादक का कुल घरेलू उत्पादन में \*\*\*% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, आवेदक उत्पादक और समर्थकों का सामूहिक रूप से घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है तथा आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

## ड. गोपनीयता

### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं। घरेलू उद्योग ने अपने वितरण चैनल का प्रकटन नहीं किया है और क्या वे ऐसे चैनल का भाग बनने वाले एजेंटों को कोई कमीशन देते हैं। ऐसे एजेंटों ने भी कोई प्रश्नावली दायर नहीं की है।

### ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत घरेलू उद्योग ने यह प्रकटन किया है कि उसने कमीशन का भुगतान किया है। प्राधिकारी को आवेदन प्रपत्र के तहत वितरण चैनल या ऐसे चैनल का भाग बनने वाले एजेंटों के बारे में आंकड़ों की आवश्यकता नहीं थी।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी

सूचना को गोपनीय समझा गया है और उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों को एक-दूसरे से ई-मेल के माध्यम से उनके अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर साझा करने के लिए निर्देश देते हुए हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

## च. विविध मुद्दे

### च.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध

32. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में एकाधिकारिक बाजार का निर्माण होगा और जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का एक स्पष्ट मामला है।
- (ii) पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि होगी।
- (iii) आयात के अभाव में घरेलू उद्योग चीनी, वस्त्र और कागज उद्योग की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा।
- (iv) याचिका में उल्लिखित अधिकतर निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
- (v) घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामान की मौसमी और भौगोलिक मांग के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं। तदनुसार, जांच की अवधि 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष के रूप में निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि उत्पाद एक मौसम में विफल हो सकता है।
- (vi) विचाराधीन उत्पाद पानी के संपर्क में आने पर खतरनाक और अत्यधिक दहनशील होता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का भंडारण और परिवहन कठिन होता है, विशेष रूप से वर्षा ऋतु में, उस अवधि के दौरान मांग कम हो जाती है।
- (vii) विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग मुख्य रूप से गुजरात में वस्त्र/डेनिम कारखानों में किया जाता है, जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई या तो आंशिक रूप से बंद हैं या भुगतान में विलंब आया है।
- (viii) विचाराधीन उत्पाद का उपयोग उत्तर भारत और महाराष्ट्र में चीनी कारखानों में किया जाता है जिनकी वित्तीय स्थिति हमेशा खराब रही है।
- (ix) घरेलू उद्योग को सरकार से रियायतें और कर लाभ मिल रहे हैं।
- (x) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के साथ-साथ मेलामाइन से संबंधित जांच में संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को एक हितवद्ध पक्षकार माना है और इस संबंध में आज तक कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया है।
- (xi) जांच की अवधि के दौरान, कंपनी ने \*\*\* मूल्य के \*\*\* कि. ग्रा. संबद्ध सामानों की खरीद की है।
- (xii) घरेलू उद्योग ने अपने संयंत्र के स्थान में परिवर्तन के लागत और प्रभावों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- (xiii) एस्को ग्रुप विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक नहीं है।
- (xiv) सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट भी आवेदक की वेबसाइट के अनुसार ज़िंक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री है, लेकिन याचिका में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।
- (xv) घरेलू उद्योग तीन उप-उत्पादों की पेशकश करता है, अर्थात् सोडियम फॉर्मेट, सोडियम सल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट, जिन्हें 'ट्रीसाल्ट्स' के रूप में जाना जाता है।
- (xvi) सिलोक्स एस. ए और सिलोक्स बेल्जियम, जो आवेदक की समूह कंपनियां हैं, विचाराधीन उत्पाद को पूरे विश्व में निर्यात करती हैं लेकिन भारत को निर्यात नहीं करती हैं।

- (xvii) आवेदक की विभिन्न धारक कंपनियों, जैसे कि सिलिकॉस होल्डिंग, सिलोक्स यूके, सिलोक्स इंडिस, सिलोक्स एसए, सिलोक्स बेल्जियम, एचटीसीआई, श्रॉफ ग्रुप, प्रायोन, साइबेले, ओसीपी और एसआरआईडब्ल्यू ने प्राधिकारी के पास कोई सूचना दायर नहीं की है।
- (xviii) घरेलू उद्योग ने अपनी अगोपनीय याचिका में विश्लेषण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं।

## च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) संदीप ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक हितवद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि कंपनी मेरिनो पैन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ऑटोमेटेड टायर्स इंपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेमटेड के निर्णय के अनुरूप, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने में विफल रही है। इसके अतिरिक्त, संदीप ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के 2017-18 से 2019-20 के वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी ने शून्य आयात किया है।
- (ii) देश में मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास देश में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- (iii) उपभोक्ताओं की भागीदारी के अभाव में और केवल एक पक्षकार जो आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने में विफल रहा, की भागीदारी का उपभोक्ताओं पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- (iv) विचाराधीन उत्पाद एक कच्ची सामग्री नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए एक मात्र रासायनिक या योजक है जो उत्पादन लागत में केवल एक सीमित हिस्से का निर्माण करता है और इस प्रकार, शुल्क लगाने से निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि नहीं होगी।
- (v) घरेलू उत्पादकों के बीच काफी परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ देश में एक स्वस्थ बाजार स्थिति मौजूद है, जो उपभोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराती है।
- (vi) उस अवधि के दौरान जब चीन पर शुल्क लगाया गया था, गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि, उचित बाजार स्थितियों में भारत को सामग्री की आपूर्ति करने के लिए तीसरे देशों की इच्छा को दर्शाती है।
- (vii) शुल्क लगाने से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा के संरक्षण में मदद मिलेगी।
- (viii) घरेलू उद्योग चीनी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है जिनकी लागत और कीमतें सरकारी हस्तक्षेप से गंभीर रूप से विकृत हैं, जो इस तथ्य से सिद्ध है कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का कोई दावा नहीं है।
- (ix) विचाराधीन उत्पाद वस्त्र उद्योग में उत्पादन लागत का केवल एक न्यूनतम हिस्सा है जो डेनिम के उत्पादन की कुल लागत का 0.02% है और इस प्रकार, कीमत में मामूली वृद्धि से उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (x) हितवद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद का चीनी उद्योग में प्रयोग नहीं किया जाता है।
- (xi) यहां तक कि यद्यपि जर्मनी, चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामान विगत में पाटनरोधी शुल्कों के अधीन रहे हैं, तथापि 2017 में शुल्क समाप्त होने पर संबद्ध आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। विदेशी उत्पादकों द्वारा क्षतिकारक पाटन जारी रहने तक पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता है।
- (xii) चूंकि जांच की शुरुआत की अधिसूचना संबद्ध देशों के दूतावासों को भेजी गई थी, अतः यह नहीं माना जा सकता कि निर्यातक जांच से अनभिज्ञ थे।
- (xiii) हितवद्ध पक्षकारों के इस दावे के उत्तर में कि घरेलू उद्योग को सरकार से कर लाभ या छूट से लाभ हुआ है, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसा कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।
- (xiv) हितवद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई।
- (xv) हितवद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, एस्को समूह संबद्ध सामानों का एक प्रमुख उत्पादक है जिसकी इटली, यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में उत्पादन यूनिटें हैं।

- (xvi) सिलोक्स एस. ए और सिलोक्स बेल्जियम भारतीय बाजार में नहीं बेचते हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि घरेलू उद्योग के पास स्वयं की कम उपयोग की गई क्षमता है, अतः इन कंपनियों के लिए भारत को निर्यात करने का कोई अर्थ नहीं है।
- (xvii) आवेदक की समूह कंपनियां-सिलॉक्स होलिंग, सिलॉक्स यूके, सिलॉक्स एंजिस, सिलॉक्स एसए, सिलॉक्स बेल्जियम, एचटीसीआई, शॉफ ग्रुप, प्रायोन, साइबेले, ओसीपी और एसआरआईडब्ल्यू हितवद्ध पक्षकार के क्षेत्र में नहीं आती हैं क्योंकि वे न तो संबद्ध देशों में स्थित हैं और न ही वे भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातक हैं।
- (xviii) विवेक्षण का प्रमाण पत्र याचिका के साथ केवल इसलिए प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि आवेदन प्रपत्र के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग कोई और सूचना प्रदान करने के लिए तैयार है जिसकी प्राधिकारी को आवश्यकता हो।
- (xix) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के भाग के रूप में अपने संयंत्र के स्थान में परिवर्तन की लागतों और प्रभावों के संबंध में सभी ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं।

### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाने से बाजार में एकाधिकार पैदा होने की संभावना है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में देश में संबद्ध सामानों के चार उत्पादक हैं। इसलिए, देश में एकाधिकार बाजार के निर्माण की कोई संभावना नहीं दिखती। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करते, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में आए।
35. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि अधिकतर निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की सूचना भारत के राजपत्र और डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के संबंध में संबद्ध देशों के दूतावासों को विधिवत सूचित किया था। इसके बावजूद, संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए या वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया।
36. आयातक ने यह भी तर्क दिया है कि संबद्ध सामानों की मांग मौसमी है और वर्षा ऋतु में कम हो जाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में चार वित्तीय वर्ष शामिल हैं। इसलिए, यदि मांग मानसून से प्रभावित होती है, तो प्रत्येक वर्ष में ऐसा ही होगा। इसलिए, प्राधिकारी को जांच की अवधि दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाया जाता। अन्यथा भी, नियमावली जांच की अवधि को अधिकतम 18 महीने तक रखने की अनुमति देती है।
37. प्रश्नावली का उत्तर दायर करने में संदीप ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की विफलता के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 11/2018 किसी हितवद्ध पक्षकार को प्रश्नावली का उत्तर दायर किए बिना भी जांच में भाग लेने की अनुमति देती है। इसलिए, यहां तक कि यद्यपि आयातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया हो, तथापि प्राधिकारी ने संदीप ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड को वर्तमान जांच में एक हितवद्ध पक्षकार के रूप में माना है।
38. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि होगी, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद कच्ची सामग्री नहीं है, बल्कि केवल एक रसायन या एक योजक है और इसका उपयोग केवल रंगाई, विरंजन, या कम करने वाले एजेंट/ऑक्सीजन स्केविजिंग एजेंट के रूप में, या रंग छुड़ाने के लिए किया जाता है और निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए उत्पादन लागत का प्रमुख भाग नहीं है। अतः, शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं के लिए लागत में काफी वृद्धि नहीं होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य देने के लिए जांच में भाग नहीं लिया है।

### छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

39. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

## च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने यह दर्शाने करने के लिए भाग नहीं लिया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (ii) चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य यूरोपीय संघ से भारत में निर्यात की कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि यूरोपीय संघ से आयात संबद्ध देशों के बाद आयात का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये आयात चीनी आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और ये आयात पाटित नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार, यूरोपीय संघ कुइटुन जिंजियन केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश है।
- (iii) तीसरे देशों को निर्यात कीमत की उपलब्धता के बावजूद भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क(1)(ग) के अनुरूप नहीं है।
- (iv) प्राधिकारी को कोरिया गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश को निर्यात कीमत के आधार पर करना चाहिए जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में है। यदि निर्यात कीमतें जांच की शुरुआत के समय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोरियाई उत्पादकों की उत्पादन लागत से अधिक हैं, तो ऐसी बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (v) उपयुक्त तीसरे देश का निर्धारण करने के लिए यूएसडीओसी पांच प्रतिशत परीक्षण लागू करता है, चाहे निर्यात समान उत्पादों का हो और चाहे बिक्री की मात्रा अन्य देशों की बिक्री की मात्रा से अधिक हो। चूंकि जापान को निर्यात की मात्रा अन्य देशों को निर्यात की मात्रा से अधिक है, अतः जापान को एक उपयुक्त तीसरा देश माना जाए और सामान्य मूल्य कोरिया गणराज्य से जापान को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाए।
- (vi) यदि प्राधिकारी भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं, तो उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया जाना चाहिए न कि उत्पादन की इष्टतम लागत पर। इष्टतम लागत उत्पादन को अपनाता निर्यातकों को वर्तमान जांच में उनकी गैर-प्रतिभागिता के लिए पुरस्कृत करता है।
- (vii) निर्यात कीमत का निर्धारण सीआईएफ कीमत के आधार पर किया गया है जिसे कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा के लिए समायोजित किया गया है।
- (viii) संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

**छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

42. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम विक्री मात्रा के कारण ऐसी विक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
  - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
  - (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्भूत वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

43. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके इस जांच में सहयोग नहीं किया है।

**छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण****चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

44. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद है: प्रावधान निम्नलिखित में 15

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994("पाटनरोधी समझौता"-अनुच्छेद के (VI) के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सस्मिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
45. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत प्रावधान में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।
46. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित है:
- "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"
47. आवेदन पत्र के स्तर पर, आवेदक ने चीन जन. गण. के लिए यूरोपीय संघ को प्रतिनिधि देश के रूप में दावा किया था। आवेदक ने दावा किया कि विचाराधीन उत्पाद प्रमुख रूप से तीन क्षेत्रों, चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ से उत्पादित और निर्यातित किया जाता है। चूंकि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य पहले से ही वर्तमान आवेदन पत्र के विषय हैं, अतः आवेदक ने दावा किया कि यूरोपीय संघ एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तदनुसार, आवेदक ने यूरोपीय संघ में प्रचलित कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया। तथापि, जांच के दौरान, आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत को निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य भी दिया है।



48. यह नोट किया जाता है कि कानून में दिए गए अनुक्रम के अनुसार, सामान्य मूल्य पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। जहां सामान्य मूल्य एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश को संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्रुत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, जबकि आवेदक ने यूरोपीय संघ में प्रचलित कीमतों के संबंध में सूचना दी है, वह यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि यूरोपीय संघ में विकास का स्तर चीन जन. गण. के विकास के स्तर से तुलनीय है। तदनुसार, यूरोपीय संघ और चीन जन. गण. के विकास के स्तर की तुलना के संबंध में किसी भी सूचना के अभाव में, यूरोपीय संघ में प्रचलित कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।
49. आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत में संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का भी दावा किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सेस्टेट के जांच परिणामों को नोट करते हैं, जिसमें यह माना गया था कि जब सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यात के आधार पर किया जाता है तो उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का निर्धारण करने के लिए संगत मानदंड ऐसे देश से निर्यात की मात्रा है और जांच की अवधि के दौरान उस देश को पाटन नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से काफी आयात हो रहे हैं, जो न्यूनतम सीमा से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ से आयातों को पाटित नहीं माना जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी यूरोपीय संघ से शेष विश्व में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित मानते हैं।
50. इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ से शेष विश्व में निर्यात के लिए डब्ल्यूटीए आंकड़ों पर विचार किया है। चूंकि ये कीमतें एफओबी स्तर पर हैं, अतः कारखानागत कीमत निकालने के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत को कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़े के निमित्त समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

### कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

51. कोरिया गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में कोरिया गणराज्य में उत्पादकों की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने कोरिया गणराज्य से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के संबंध में सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अनुरोध किया है कि कोरिया गणराज्य से निर्यात के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया को लागू किया जाए। प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों और उत्पादन क्षमताओं के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोरिया गणराज्य में उत्पादकों की उत्पादन लागत का निर्धारण किया है। उत्पादन की इस लागत की तुलना कोरिया गणराज्य से निर्यात कीमत से की गई है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या निर्यात व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किये गये हैं।
52. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या लाभप्रद निर्यातों की मात्रा मात्रा में पर्याप्त है, अर्थात् क्या यह भारत को निर्यात की मात्रा के कम से कम 5% से अधिक है। व्यापार परीक्षण और पर्याप्तता परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया को लागू करने के बाद, प्राधिकारी पाते हैं कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात पर विचार किया जा सकता है। चूंकि जापान को निर्यात की मात्रा इन देशों में सबसे अधिक है, अतः प्राधिकारी इसे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त तीसरे देश के रूप में विचार करना उचित मानते हैं। कोरिया गणराज्य से जापान को निर्यात कीमत को कारखानागत कीमत निकालने के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतर्देशीय भाड़े के निमित्त समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

### छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

#### चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

53. चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के अनुसार

सीआईएफ कीमत पर विचार किया गया है, जिसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा के लिए समायोजित किया गया है।

### कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

54. कोरिया गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ कीमत पर विचार किया गया है, जिसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा के लिए समायोजित किया गया है।

### छ.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

55. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्रम सं.	देश	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अमे. डॉ./मी. टन)	(अमे. डॉ./मी. टन)	(अमे. डॉ./मी. टन)	(%)	(रेंज)
1	चीन जन. गण.	***	***	***	***	70-80
2	कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	60-70

### ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच

#### ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

56. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान अपने संयंत्र को अटलदरा से एकलवारा में स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि पूर्व क्षेत्र को सरकार द्वारा आवासीय घोषित किया गया था। नया संयंत्र फरवरी, 2017 के अंतिम समाह में चालू किया गया था और यह जस्ता मार्ग के माध्यम से संबद्ध सामानों का उत्पादन करता है।
- घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच चीन जन. गण. से आयातों पर लगाए गए शुल्कों, जो 2017 में समाप्त हो गए थे, की समाप्ति के प्रभाव तथा कोरिया गणराज्य और जर्मनी से आयातों पर जो 2014 में समाप्त हो गए थे, की समाप्ति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, जिसके बाद आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई।
- संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में 667% की वृद्धि हुई है और अकेले चीन जन. गण. से आयातों में क्षति अवधि के दौरान 145 गुना तक वृद्धि हुई है।
- उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा में भी क्रमशः 654% और 613% तक काफी वृद्धि हुई है।
- आयात में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। जबकि मांग में 7% तक वृद्धि हुई, आयात की मात्रा में 667% तक वृद्धि हुई।
- आयात की मात्रा पूरी तरह से अनावश्यक है क्योंकि कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है और घरेलू उद्योग आत्मनिर्भर है।
- संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत में 2018-19 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान 20% तक गिरावट आई और यह क्षति अवधि में सबसे कम थी, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा हुई। इसके अतिरिक्त, जबकि संबद्ध देशों से कीमतों में गिरावट आई है, गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमतों में वृद्धि हुई है।

- (viii) घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामान को लागत से कम पर बेचने के बावजूद आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती हो रही है।
- (ix) जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में 2018-19 तक वृद्धि हुई, जांच की अवधि में दोनों में गिरावट आई। तथापि, बिक्री कीमतों में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग लागत के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ था और पहुंच कीमत में गिरावट के कारण अपनी कीमतों से समझौता करने के लिए मजबूर था।
- (x) घरेलू उद्योग ने 2017-18 में अपनी क्षमता में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप उनकी निर्धारित लागतों में वृद्धि हुई लेकिन लागत वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।
- (xi) जबकि जांच की अवधि में संस्थापित क्षमता में वृद्धि हुई, उत्पादन और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में गिरावट आई।
- (xii) इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में केवल 4% तक वृद्धि हुई जबकि मांग में 7% तक वृद्धि हुई।
- (xiii) घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई जबकि आयातों के बाजार हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई।
- (xiv) जांच की अवधि में मालसूची में वृद्धि हुई।
- (xv) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 300% से अधिक तक गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।
- (xvi) घरेलू उद्योग ने क्षमता को छोड़कर अपने कीमत मानदंडों और मात्रा मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- (xvii) संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि घरेलू उद्योग का ब्याज पूर्व लाभ नकारात्मक है।
- (xviii) घरेलू उद्योग को किन्हीं अन्य कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है।
- (xix) पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है।
- (xx) अन्य घरेलू उत्पादकों के राजस्व और लाभप्रदता में भी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- (xxi) इस तर्क के संबंध में कि कोरिया गणराज्य से आयात क्षतिकारक नहीं हैं, यह अनुरोध किया गया था कि कोरिया गणराज्य से आयात देश में कुल आयात का 3% से अधिक हैं तथा घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर हैं।
- (xxii) इस दावे के उत्तर में कि चीन जन. गण. में कारखाने बंद हो गए हैं, यह अनुरोध किया गया था कि चीन से आयातों ने इस प्रकार की बंदी को ध्यान में रखते हुए काफी वृद्धि दर्शाई है। इसके अतिरिक्त, बंदी यिचांग, हुबेई प्रांत तक सीमित थी और चीन के अन्य हिस्सों में कोई बंदी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इस संबद्ध सामान के सबसे बड़े उत्पादक गुआंग्डी केमिकल्स ने क्षमता बढ़ाई है जिसके 2019 तक प्रचालनात्मक होने की उम्मीद है।
- (xxiii) हितवद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत संबद्ध देशों से निर्यात कीमत भारत से तीसरे देशों को निर्यात कीमत से कम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से निर्यात के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत 2018-19 तक घरेलू बिक्री कीमत से कम थी। तथापि, जांच की अवधि के दौरान, अत्यधिक पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात की तुलना में घरेलू कीमत कम हुई।
- (xxiv) आवेदक को क्षति उसकी अंतर्निहित अदक्ष कीमत निर्धारण नीतियों के कारण नहीं है, जैसा कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है, क्योंकि आवेदकों के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है और बाद में चीन जन. गण. से आयातों पर शुल्क की समाप्ति और पाटित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि से गिरावट आई।
- (xxv) हितवद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, जांच की अवधि के दौरान जापान से कोई आयात नहीं हुआ है; इसलिए जापान से निर्यात को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
- (xxvi) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग पुरानी मशीनरी का प्रयोग कर रहा है, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने लगातार अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया है और हाल ही में सल्फर डाइऑक्साइड प्रौद्योगिकी प्राप्त

की है। किसी भी दशा में, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को उसी रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जैसी वह मौजूद है।

(xxvii) घरेलू उद्योग में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों का निर्धारण कार्यगत आधार पर किया जाता है और इसमें शामिल भाड़ा प्रभावों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

## ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

57. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) किसी विशेष क्षेत्र में उत्पाद की मौसमी मांग के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग कीमत निर्धारण नीति के कारण घरेलू उद्योग को हानियां हो रही हैं।
- (ii) घरेलू उद्योग एक अंतिम प्रयोक्ता और एक व्यापारी को भिन्न-भिन्न कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराता है।
- (iii) घरेलू उद्योग को हानियां हो रही हैं क्योंकि यह पुराना है और अप्रचलित प्रौद्योगिकी एवं मशीनों का प्रयोग कर रहा है।
- (iv) कोरिया गणराज्य से आयात महंगे हैं तथा आपूर्ति अनियमित और कम है।
- (v) चीन जन. गण. में कई कारखाने उच्च लागत और अत्यधिक प्रदूषण के कारण बंद हो गए हैं।
- (vi) घरेलू उद्योग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की सहित अन्य देशों को निर्यात पर विचार किया जाना चाहिए, जो कि संख्या में अधिक हैं, जिसका अर्थ है कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य भारत की तुलना में महंगे हैं। इसके अतिरिक्त, तूतीकोरिन से निर्यात किया जा रहा है लेकिन बडोदरा से नहीं।
- (vii) बीएसएफ, ब्रुगेमैन और जापान से निर्यातों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति ऐसे आयातों के कारण हो सकती है।
- (viii) चूंकि घरेलू उद्योग का संयंत्र बडोदरा में स्थित है, अतः भारत के अन्य हिस्सों में उपभोक्ताओं से अतिरिक्त परिवहन के कारण अतिरिक्त प्रभाव लिया जाता है।
- (ix) घरेलू उद्योग ने फिल्टर ड्रायर और अन्य संतुलन उपकरण जोड़कर अपनी उत्पादन क्षमता को 4600 टन से बढ़ाकर 14800 टन प्रति वर्ष कर दिया है, और लगातार अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के कारण, वे उच्च उत्पादन प्राप्त करते हुए उत्पाद के प्रति वैच उपज बढ़ाने में सक्षम थे।

## ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

58. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का निम्नलिखित रूप में समाधान करता है।

### I. संचयी मूल्यांकन

59. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयातों की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक हैं, और
- ख) आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध सामान भारत में संबद्ध देशों से पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से ही अधिक सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

61. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभावों का मूल्यांकन करना उपयुक्त है।
62. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल विक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
63. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकार के विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों एवं लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

## II. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

64. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्री की मात्रा तथा सभी स्रोतों से आयातों के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की विक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	103	104
अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	98	96
संबद्ध आयात	मी. टन	853	1,376	4,656	6,540
अन्य आयात	मी. टन	2,374	1,568	450	418
कुल मांग	मी. टन	46,608	46,402	48,389	50,094

65. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में 2017-18 में मामूली गिरावट आई लेकिन उसके बाद और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई।

## III. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश	मी. टन	853	1,376	4,656	6,540
चीन जन. गण.	मी. टन	43	710	4,080	6,288
कोरिया गणराज्य	मी. टन	810	666	576	252
अन्य आयात	मी. टन	2,374	1,568	450	418
के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	1.60%	2.36%	8.11%	12.03%
खपत	%	1.83%	2.97%	9.62%	13.05%
कुल आयात	%	26.43%	46.75%	91.19%	93.99%

67. यह नोट किया गया है कि:

- पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई थी और जांच की अवधि के दौरान यह अधिकतम थी। इस अवधि में आयातों में 667 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में भी जांच की अवधि में 90 प्रतिशत से अधिक की प्रबल रूप से वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान यह सीमान्त थे।

#### IV. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी मात्रा तक कमी करना है या कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से की गई है।

#### क. कीमत कटौती

69. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए, उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूटों और करों के निवल, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
चीन जन. गण.					
निवल बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	126	105
पहुँच कीमत	₹/मी. टन	52,354	89,875	83,229	66,889
कीमत कटौती	₹/मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***

कीमत कटौती	रेंज	45-55	(0-10)	10-20	20-30
कोरिया गणराज्य					
निवल विक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	126	105
पहुँच कीमत	₹/मी. टन	68,646	68,693	86,634	76,938
कीमत कटौती	₹/मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	20-30	10-20	0-10
संबद्ध देश					
निवल विक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	126	105
पहुँच कीमत	₹/मी. टन	67,825	79,626	83,650	67,276
कीमत कटौती	₹/मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	0-10	10-20	20-30

70. यह नोट किया गया कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम कीमत पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

**ख. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास**

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों का काफी मात्रा तक ह्रास करने के लिए है अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की तुलना पहुँच मूल्य से की गई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	116	126	123
विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	111	126	105
संबद्ध देश से पहुँच कीमत	रु./मी. टन	67,825	79,626	83,650	67,276
प्रवृत्ति		100	117	123	99

72. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत और विक्री कीमत, दोनों में, क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, विक्रियों की लागत में वृद्धि विक्री कीमत में वृद्धि की तुलना में अधिक उच्च दर पर थी। तुलना करने पर, आयातों की पहुंच कीमत में इस अवधि में गिरावट आई है। अतः संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

#### V. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

73. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

#### क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री

74. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	105	127
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	114	111
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	108	88
घरेलू विक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	103	104

75. यह देखा गया है कि:

- 2018-19 में घरेलू उद्योग की क्षमता में गिरावट आई है किन्तु घरेलू उत्पादक द्वारा क्षमता विस्तार के कारण जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है।
- 2017-18 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु उसके बाद 2018-19 और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान, क्षमता में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट दर्शायी है।
- क्षमता में गिरावट के कारण 2018-19 में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान दुबारा कमी आई है।
- 2018-19 में घरेलू उद्योग की विक्रियों में गिरावट आई किन्तु जांच की अवधि में इसमें मामूली वृद्धि हुई।



**ख. बाजार हिस्सा**

76. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा नीचे दिया गया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	99	97
समर्थक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	94	89
संबद्ध आयात	%	1.83%	2.97%	9.62%	13.05%
अन्य आयात	%	5.09%	3.38%	0.93%	0.83%

77. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है किंतु संबद्ध अन्य आयातों के हिस्से में गिरावट आई है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2017-18 तक वृद्धि हुई है। किंतु उसके बाद इसमें गिरावट आई है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान समग्र रूप में भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है।

**ग. मालसूची**

78. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
प्रारंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	69	117

79. यह नोट किया गया है कि 2017-18 में भारतीय उद्योग की मालसूची में गिरावट हुई किन्तु जांच की अवधि में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

**घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय**

80. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	126	123
विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	126	105
कर पूर्व लाभ	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	17	126	(233)
कर पूर्व कुल लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	18	129	(243)
ब्याज और करों पूर्व कुल लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22	128	(228)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	160	(81)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	10	77	(115)

81. यह देखा गया है कि:-

- घरेलू उद्योग के लाभों में 2018-19 में वृद्धि हुई थी किन्तु जांच की अवधि में इसमें ह्रास आया। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग ने भारी हानि का सामना किया है।
- घरेलू उद्योग के नकद लाभों में 2018-19 तक वृद्धि हुई थी किन्तु घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नकद हानियों का सामना किया है।
- घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में भी गिरावट आई है, यह जांच की अवधि में नकारात्मक थी।

#### ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

82. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच निम्नलिखित रूप में की है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	107	94
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	114	111
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	106	119
प्रति यूनिट मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	84	101

83. यह देखा गया है कि 2017-18 में घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई थी किन्तु उसके बाद उसमें गिरावट आई, किन्तु मजदूरी में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, इस अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है।

**छ. वृद्धि**

84. घरेलू उद्योग की मात्रा की प्रवृत्ति और लाभ मानदंड निम्नलिखित हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	17%	-3%	-2%
घरेलू विक्रियां	%	-	8%	-5%	2%
लाभ	%	-	-62%	292%	-265%
नकद लाभ	%	-	12%	57%	-148%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-78%	300%	-220%

85. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। जहां घरेलू उत्पादन के नकारात्मक वृद्धि दर्शाया है, वहीं जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्रियों में मामूली वृद्धि हुई है, जब पिछले वर्ष से इसकी तुलना की जाती है। इसके अलावा, जांच की अवधि में लाभप्रदता पैरामीटरों ने महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि दर्शाया है।

**छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को काफी हानियां हो रही हैं और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हो रही है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता संबद्ध आयातों से स्पष्ट रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

**ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

87. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग पहुंच कीमत में गिरावट के कारण अपनी विक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

**झ. पाटन की मात्रा**

88. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक एवं काफी है।

**झ. क्षति मार्जिन की मात्रा**

89. प्राधिकारी ने अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी की जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना कर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की संभावना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी को निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, यूटिलिटीज और क्षमताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण या अनावर्ती व्ययों को प्रभावित नहीं किया गया था। पीयूसी के लिए औसत नियोजित पूंजी पर (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियों सहित औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) को क्षति रहित कीमत पर पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, जैसा कि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और अनुसरण किया जा रहा है।

90. जैसाकि ऊपर निर्धारित किया गया है, पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और इसे नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है।

**क्षति मार्जिन सारणी**

क्रम सं.	देश	क्षति रहित	पहुँच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(रु./मी. टन)	(रु./मी. टन)	(रु./मी. टन)	(%)	(रेंज)
1	चीन जन. गण.	***	66,889	***	***	30-40
2	कोरिया गणराज्य	***	76,938	***	***	20-30

**ज. गैर-आरोप्य विश्लेषण**

91. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। जो कारक संगत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच भी की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

**क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें**

92. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर, यूरोपीय संघ से काफी आयात हैं। तथापि, ऐसे आयातों की कीमत संबद्ध देशों से आयातों की कीमत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी अधिक है। यूरोपीय संघ को छोड़कर, केवल हांगकांग से आयात हैं, जो मात्रा में नगण्य हैं। इसलिए, इन देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।

**ख. मांग में संकुचन**

93. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संभावित संकुचन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

**ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

94. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

**घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी अथवा प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं, जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान दे सकें।

**ङ. प्रौद्योगिकी में विकास**

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके।

**च. निर्यात निष्पादन**

97. प्राधिकारी ने केवल क्षति आकलन के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में कोई संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।

**छ. उत्पादकता**

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में केवल उत्पादन में गिरावट के कारण गिरावट आई है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति इस निमित्त नहीं है।

**ज. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन**

99. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष**

100. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- i. भारत में संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण पाटन है, जिसके परिणामस्वरूप पाटित आयातों की मांग में वृद्धि हुई है।
- ii. पाटित आयातों की मात्रा में कुल रूप में साथ ही उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- iii. जहां संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, घरेलू उद्योग ने अपने बाजार हिस्से को खोया है।
- iv. परिणामस्वरूप, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- v. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है।
- vi. आयातों ने घरेलू उद्योग को घटी कीमतों पर अपने माल को बेचने पर विवश किया है और घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।
- vii. घरेलू उद्योग ने हानियों, नकद हानियों और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना किया है।
- viii. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंड ने जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है।

**क. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां****क.1 अन्य हितबद्ध प्रकरणों द्वारा किए गए अनुरोध**

101. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और शुल्क के प्रभाव के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि उत्पाद विभिन्न वर्षों से शुल्क के अध्वधीन है।

**क.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

102. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियों में निम्नानुसार अनुरोध किया है:

- क. क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित अनिवार्य तथ्यों, जो निर्णय के आधार पर निर्माण करेंगे, का प्रकटन नहीं किया गया है।
- ख. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 के अनुसार और जैसाकि चीन – जीओईएस(यूएस), यूरोपियन समुदायों – फार्मिड सालमोन (नार्वे) के मामले में और निरमा लिमिटेड बनाम यूनियर ऑफ इंडिया के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, प्रकटीकरण विवरण में ऐसे अनिवार्य तथ्यों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष शामिल होंगे जो इसके निर्णय कि क्या निश्चयात्मक उपायों को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। इसलिए, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित तथ्यों का प्रकटन किए जाने की जरूरत है। यह अपने हितों की रक्षा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि है।
- ग. शुल्क अवधि लम्बी होने के बावजूद संबद्ध देशों के उत्पादकों ने, यह दर्शाते हुए कि ऐसा व्यवहार अस्थायी नहीं है, पाटन जारी रखा है।
- घ. चीन जन.गण. के उत्पादकों की अनुमानित क्षमता 1.29 मिलियन एमटी है जो 0.5 मिलियन एमटी की वैश्विक मांग से काफी अधिक है, और इसकी वजह से सीमित मांग के लिए कड़ी स्पर्धा होती है।
- ड. मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा, पर्याप्त मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग को कम उपयोग वाली क्षमताओं को चालू करने के लिए बाध्य किया गया था।
- च. देश में सुदृढ़ बाजार स्थिति है जिसके पास उपभोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प देते हुए घरेलू उत्पादकों के बीच यथेष्ट परस्पर प्रतिस्पर्धा है।

- छ. घरेलू उद्योग 25 से अधिक वर्षों से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और बाजार की मांगों के आधार पर लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने का प्रयास कर रहा है।
- ज. संबद्ध देशों में उत्पादक भारत में चुन-चुन कर संबद्ध वस्तुओं का ऐसी कीमतों पर विक्री कर रहे हैं जो वैश्विक बाजारों में प्रचलित कीमतों से कम हैं तथा उन कीमतों से भी कम कीमत पर बेच रहे हैं जिस कीमत पर वे स्वयं दूसरे देशों को बेचते हैं।
- झ. चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
- ञ. घरेलू उद्योग चीन के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिसकी लागत और कीमतें सरकार के हस्तक्षेप से अत्यधिक विकृत हो गई हैं तथा इस प्रकार शुल्क लगाने से व्यापार संबंधी ऐसी विकृतियों की क्षतिपूर्ति होगी।
- ट. पाटित वस्तुओं से घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति हुई है तथा शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का पुनरुद्धार करने में मदद मिलेगी तथा रोजगार का सृजन करने में मदद मिलेगी।
- ठ. विचाराधीन उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए केवल एक रसायन अथवा योजक है जो उत्पादन की लागत में केवल एक सीमिति हिस्सा बनता है।
- ड. विचाराधीन उत्पाद का केवल स्थानीय रूप से प्राप्त किए गए कच्चे-माल का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है और इस प्रकार भारतीय उद्योग कच्चे माल के उत्पादकों को भी अपस्ट्रीम हेतु बाजार उपलब्ध कराता है।
- ढ. जांच के बारे में अपनी कम चिन्ता को इंगित करते हुए किसी भी विदेशी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- ण. उपभोक्ताओं के द्वारा भाग न लोने की स्थिति में उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है। यह अनुरोध है कि विभिन्न अन्तिम उपयोग क्षेत्रों पर 20 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने का प्रभाव 0.004 प्रतिशत से 0.06 प्रतिशत होगा।
- त. जब चीन पर शुल्क लगाए गए थे, उस अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद में हुई बढोतरी बाजार की अच्छी स्थितियों में भारत के लिए सामग्री की आपूर्ति करने के लिए तीसरे देशों की उत्सुकता को दर्शाती है।
- थ. शुल्क लगाने से बाहार जा रही विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

103. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के कुछ अनुरोध पुनरावृत्ति स्वरूप के हैं। इन अनुरोधों के बारे में अन्तिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर पहले ही जांच कर ली गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त अनुरोधों के बारे में निम्नानुसार जांच कर ली है:-
104. शुल्क की अवधि के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि विगत प्रत्येक जांच में प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध अथवा पाटन अथवा क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना पायी है। वर्तमान मामले में भी, प्राधिकारी ने यथेष्ट पाटन पाया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इसलिए, शुल्क संबंधी पूर्ववर्ती इतिहास के बावजूद संबद्ध देशों के उत्पादकों ने पाटन जारी रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में, शुल्क की अवधि को ध्यान में न रखते हुए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की जरूरत है।
105. प्रकटन विवरण में ऐसे अनिवार्य तथ्यों को प्रकट नहीं किया है, जो इस बारे में हैं कि क्या क्षति अथवा कारणात्मक संबंध है, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में केवल अनिवार्य तथ्यों को ही प्रकट किया जाना आवश्यक होता है और यह किया गया है।

### ग. भारतीय उद्योग के हित

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाम करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और स्पष्ट प्रतिस्पर्धा की स्थिति सुनिश्चित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
107. प्राधिकारी ने आयातकर्ताओं, उपभोक्ताओं एवं अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने के लिए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के कार्यों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव

सहित वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उनके लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। यह नोट किया गया है कि किसी भी प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है। तथापि, अनुप्रवाह उत्पाद पर शुल्क के प्रभाव के बारे में घरेलू उद्योग ने सूचना उपलब्ध करायी है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार विभिन्न अन्तिम प्रयोक्ता खेत्रों पर 20 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव 0.004 प्रतिशत से 0.06 प्रतिशत होगा।

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को एक रसायन अथवा योजक के रूप में उपयोग किया जा रहा है और न कि कच्चे माल के रूप में और इस प्रकार इसकी लागत अनुप्रवाह उत्पाद की लागत एक छोटी सी प्रतिशतता बनती है। इसलिए शुल्क लगाने का अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
109. यह भी नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन का इतिहास है। शुल्कों के विगत इतिहास के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं का पाटन कम नहीं हुआ है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात वर्ष 2017 तक शुल्कों को आकर्षित कर रहे थे। शुल्क एक बार समाप्त होने पर विदेशी उत्पादकों ने भारतीय बाजार में दुबारा से पाटन करना आरम्भ कर दिया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण यह दर्शाते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमत उन कीमतों से काफी कम हैं जिस कीमत पर संबद्ध देशों में उत्पादक अन्य बाजारों में आपूर्ति कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, उत्पाद के बारे में आत्म-निर्भर होने के बावजूद भारत संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए एक बड़े निर्यात बाजार के रूप में उभरा है। इसलिए जब तक शुल्क नहीं लगाए जाते हैं, तब तक संबद्ध देशों में उत्पादक क्षतिकर पाटन जारी रखते रहेंगे।
110. यह स्वीकार किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में स्पष्ट प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, विशेषकर जब पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए एक जरूरी राशि तक सीमित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रक्रिया में अनुचित लाभ की समामि, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट में रोक लगेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

#### घ. निष्कर्ष

111. किए गए दावों, प्राप्त सूचना, किए गए अनुरोधों तथा इन निष्कर्षों में रिकॉर्ड किए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग के लिए पाटन एवं परिणामी क्षति का ऊपर इसमें किए गए निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि:
  - i. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का सामान्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, इसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ।
  - ii. आयातों की मात्रा में निर्वाध रूप से तथा उत्पादन और खत के संदर्भ में बढ़ोतरी हुई।
  - iii. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं।
  - iv. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रतिबंधित हुई हैं।
  - v. घरेलू उद्योग की क्षमता में बढ़ोतरी होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आयी है।
  - vi. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्रियों में सीमान्त रूप से बढ़ोतरी हुई है।
  - vii. घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है जबकि उनके आयातों में बढ़ोतरी हुई है।
  - viii. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की सामान-सूचियों में बढ़ोतरी हुई है।
  - ix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट दर्शायी गई है और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानियां, नकद हानियां, और निवेश पर नकारात्मक लाभ हुआ है।
  - x. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग के लिए क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।
  - xi. वर्तमान जांच में निर्धारित क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन से काफी कम है। चूंकि सिफारिश किया गया शुल्क, अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम के अनुसार क्षति मार्जिन पर आधारित है, इसलिए सिफारिश किया गया शुल्क पूर्णतः तर्कसंगत है और इससे अनुप्रवाह उद्योग पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

**ड. सिफारिशें**

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितवद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकर्ताओं तथा अन्य हितवद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था और संबंध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति एवं सकारात्मक पाटन मार्जिन को सुनिश्चित करते हुए प्राधिकारी का मत यह है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन एवं क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए जरूरी है।
113. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(घ) में निहित प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क सारणी के कॉलम 3 में विहित वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम 7 में दर्शायी गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं।
114. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3,3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू स्तर तक सीमा शुल्क के रूप में मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा।

**शुल्क सारणी**

क्र.सं.	टैरिफ शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादन	राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	440	यूएसडॉलर	एमटी
2	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	440	यूएसडॉलर	एमटी
3	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	कोई	300	यूएसडॉलर	एमटी
4	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	300	यूएसडॉलर	एमटी

**च. अगली प्रक्रिया**

115. केन्द्रीय सरकार के लिए इस आदेश के विरुद्ध एक अपील, जो इस सिफारिश से हो सकती है, वह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य होगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी



**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2021

**FINAL FINDINGS****Case No. AD (OI) – 29/2020****Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Sodium Hydrosulphite” originating in or exported from China PR and Korea RP.****F. No. 6/35/2020-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE**

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the AD Rules”) thereof:

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) received an application from Transpek-Silox Industry Private Limited (hereinafter referred to as the “Applicant” or “the Domestic Industry” or “the Petitioners”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) requesting for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Sodium Hydrosulphite (hereinafter also referred to as the “PUC” or “subject goods” or “product under consideration”) from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of a duly documented petition and prima-facie evidence submitted by the Applicant, issued a notification No. 6/35/2020-DGTR, dated 16<sup>th</sup> September 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods from China PR and Korea RP and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed with regards to the subject investigation:
  - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
  - b. The Authority issued a public notice dated 16<sup>th</sup> September 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from China PR and Korea RP.
  - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 16<sup>th</sup> September 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, as per the information made available by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
  - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers / exporters of the subject countries and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
  - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers / exporters from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
  - f. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating an anti-dumping investigation to the following known producers / exporters in the subject countries and opportunity to make their submissions known in accordance with the Rule 6(4) of the Rules:

- i. Jinhe Sodium Hydrosulfite Factory Co. Limited, China PR
- ii. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co. Limited, China PR
- iii. Hainan Zhongxin Chemical Co. Limited, China PR
- iv. Jinhe Sodium Hydrosulfite Factory Co. Limited, China PR
- v. CNSG Anhui Hong Sifang Co. Limited, China PR
- vi. Zhejiang Huidelong Chemical Co. Limited, China PR
- vii. Zhejiang Runtu Co. Limited, China PR
- viii. Anhui Choloro Alkali Chemical Group Co. Limited, China PR
- ix. Anyang Chemical Industry Co. Limited, China PR
- x. Hansol Chemical, Korea RP
- xi. Poohung Photo-Chemical Company Limited, Korea RP
- g. None of the exporters/ producers has filed response to the exporter's questionnaire.
- h. The Authority sent Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
  - i. Morarjee Brembana
  - ii. Modern Denim
  - iii. Madura Coats Limited
  - iv. EICL Limited
  - v. Reliance Textile Industries Limited
  - vi. Welspun Terry Towels
  - vii. Andhra Pradesh Paper Mills Limited
  - viii. Everest Organics Limited
  - ix. Vardhman Fabrics
  - x. Orchid Pharma
- i. The Authority also sent notification to the following Associations asking them to intimate all their members regarding the initiation of the investigation and submit response comments, if any
  - i. Indian Cotton Mills Federation
  - ii. The Textiles Association of India
  - iii. Ahmedabad Textiles Industries Research Association
  - iv. The Gujarat Dyestuff Manufacturing Association
  - v. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
  - vi. Confederation of Indian Industry (CII)
  - vii. Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
- j. None of the importers and users of the subject goods have filed questionnaire response. Sandeep Organics Private Limited has filed submissions during the course of the investigation as an importer.
- k. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 2020 (12 months). The injury analysis period includes 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.
- l. Transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the DGCI&S. The Authority has relied upon data of DGCI&S for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- m. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

- n. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- o. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 21<sup>st</sup> June 2021 through video conferencing. The interested parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- q. The submissions and arguments made by the interested parties and the information provided by the various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
- r. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings, by verifying the data / documents submitted by the domestic industry to the extent possible.
- s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- u. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 9<sup>th</sup> September, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- v.\*\*\* in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.65.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

*“Sodium Hydrosulphite”, whether produced using Zinc or Sodium Formate, also known as “Hydrosulphite Concentrate” or “Sodium Dithionite” or “Sodium Hydrosulfite” or “SHS”. It is a white or grayish white powder, free from visible foreign particles with pungent odour. Its crystalline chemical formula is  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ . It is used in diverse industrial sectors like Textiles, Soap, Molasses, Glue and reducing agent.*

*4. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under the tariff heading 28311010 and 28321020. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”*

**C.1. Submissions of the other interested parties**

5. The other interested parties have submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and like article.
- i. The product imported from China PR and Korea RP are different from the product manufactured by the domestic industry, as has been admitted by the applicant on their website but has not been stated in the petition.
  - ii. The products produced using zinc process are different than those produced using sodium formate process in terms of demand, usage, production process, cost and selling price. Production through zinc process is costlier and uncommon in trade while production through formate process is more common, which is used in China PR.
  - iii. The products manufactured through zinc and sodium formate processes have different density as per the website of the applicant, but the same has not been disclosed in the petition.
  - iv. Due to free-flowing machines, China PR produces SHS only through SF route and further, Chinese government has banned zinc manufacturing units 3 years ago. Thus, there are no imports of SHS (Zn) at all.
  - v. The domestic industry has not specified the production route used by producers in Korea RP.
  - vi. TCP India manufactures the product using sodium formate process and have admitted on their website that such products have an advantage over products produced using zinc or amalgam process since they do not contain even traces of zinc, iron or mercury. Further, the domestic industry has failed to provide details of amalgam process in their petition.
  - vii. The price, demand and usage of the product under consideration varies based on packing. Exports from China PR are offered in 50 kgs packing which is costlier and more common in trade while the domestic industry offers wide range from 1 kg to 100 kgs packing as well as large size packings in mild steel drums and HMHDPE carboys. For exports, domestic industry offers two packings, 50 kg and 100 kg in mild steel drums, with and without pallets.
  - viii. Price and usage of the products also varies as per form, either in powder form or lumps, which has not been disclosed by the applicant.
  - ix. The assay value of the product imported from Korea RP is minimum 90% only and that of product imported from China PR is minimum 85-88%, with 88% purity being the most common in trade. Price, demand, supply and usage of the product under consideration varies as per purity and as the purity increases, the price also increases.
  - x. The domestic industry has not provided information on whether they produce product with assay level of 85%, 90% and Grade E, which constitute the subject imports and whether there exists any difference between their product and imports.
  - xi. The domestic industry has not disclosed in their petition that Thiourea dioxide is a substitute of the product under consideration.
  - xii. Domestic industry has not disclosed the difference between Hydros D and Leucosafe D7.
  - xiii. The product produced by the domestic industry does not have a BIS certificate.

**C.2. Submissions of the domestic industry**

6. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article.
- i. The product under consideration is Sodium Hydrosulphite (SHS), whether produced using Zinc or Sodium Formate process. It is also known as Hydrosulphite Concentrate or Sodium Dithionite or Sodium Hydrosulfite ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ) and is classifiable under the custom codes 28311010 and 28321020.
  - ii. Goods are produced in China and in India using both Zinc route and Sodium Formate route and both the products are used as substitute for each other by the consumers who do not consider the products manufactured through different routes as different despite the price for the product produced through zinc route being slightly higher.
  - iii. Since the product does not form a major part of the cost of the consumers, the consumers tend to give preference to convenience and other factors instead of the price of a particular product.
  - iv. The products using the Zinc process and Sodium formate process can be used interchangeably in a number of applications While the users in the denim (textile) and jaggery industry prefer the product

- produced using zinc route due to properties such as low dusting, better stability, etc., but such consumer are limited and the majority of consumers use the products interchangeably.
- v. The import data does not permit segregation of the goods produced through Sodium formate route or the Zinc route, based on the descriptions.
  - vi. The goods produced by the domestic industry were considered as like articles to the goods imported from China PR and Korea RP in the previous investigations.
  - vii. The producers in China PR are producing the product using both the processes.
  - viii. Even though the denim textile industry prefers the goods produced using the Zinc route, the other consumers focus on the cheaper product rather than on the production process of the product. The imported goods and the domestic industry include products produced using the Zinc route.
  - ix. The domestic industry produces the subject goods from the Zinc and the Sodium formate route, which are largely the same in chemical composition and used interchangeably. As TCP India is not part of the domestic industry, the process used by it is irrelevant.
  - x. Contrary to the contention made by the interested parties, no claim has been made by the applicant in their website that there is a difference in density of the products manufactured through Zinc and Sodium formate.
  - xi. The domestic industry holds no obligation to specify the route of the production as the same cannot be identified from the import data. Further, the importer has neither quantified nor established impact of possible differences in the production process.
  - xii. The domestic industry produces the product under consideration with assay level of 88% and 84%, while other domestic producers produce goods ranging from 70-92%.
  - xiii. Though the purity of goods produced by Gulshan Chemicals is irrelevant, it produces subject goods with assay level of 85%, 88% generally and 90% on demand.
  - xiv. The applicant has supplied the subject goods only in 50 kg packaging as the 100 kg packaging was discontinued, based on customer preference.
  - xv. There is no link between the price and purity of the product as both the products of lower purity are sold at a higher price.
  - xvi. Amalgam process is used for production of the subject goods only in Germany and not widely used in India or the subject countries.
  - xvii. The product Hydros-D produced by the applicant is a specialty product which performs better in indigo dyeing of denims due to additional enhancements. Despite being more advanced, the product produced by the domestic industry essentially has the same characteristics and composition as the imported goods. No inference can be drawn regarding comparability of the product under consideration and the domestic product as a whole based on one variant.
  - xviii. Hydros D and Leucosafe D7 are 2 specialty variants of the product under consideration, with no differences in terms of chemical composition, while in terms of price, the former is priced higher.
  - xix. Sodium Hydrosulphite is not available in the form of lumps and is sold only as powder, as such the price and usage of the products does not vary by form as claimed by the interested parties.
  - xx. Grade E product is a brand of BASF, Germany and is not imported from the subject countries.
  - xxi. Regarding the claim that substitute of the product was not mentioned in petition, it is submitted that Thiourea Dioxide can only theoretically be used as a substitute for Sodium Hydrosulphite but practically, it is not used by any of the downstream users in India owing to the poor performance. In any case, the demand for the subject good has increased significantly and the injury is not caused by the price of an alleged identical substitute.
  - xxii. Contrary to the allegation by the interested parties, the product manufactured by the domestic industry is BIS certified.
  - xxiii. Regarding the contention that Sodium Sulphite, Sodium Sulfate and Sodium Thiosulfate were not disclosed as raw material, it is submitted that these are not raw materials for the product under consideration but added as stabilizing agents and are not used to manufacture the product under consideration.

**C.3. Examination by the Authority**

7. The product under consideration in the present investigation is "Sodium Hydrosulphite.", whether produced using Zinc or Sodium Formate, is also known as "Hydrosulphite Concentrate" or "Sodium Dithionite" or "Sodium Hydrosulfite" or "SHS". It is a white or grayish white powder, free from visible foreign particles with pungent odour. Its crystalline chemical formula is  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ .
8. The product under consideration is produced using either "Zinc Process" or "Sodium Format Process". The former process involves reaction of zinc dust with sulphur dioxide and converting the resultant zinc salt to sodium hydrosulphite in the presence of caustic soda and soda ash. The latter process involves the reaction of caustic soda and sulphur dioxide with sodium format in a methanol solution to produce sodium hydrosulphite.
9. The product under consideration is classified under Headings 2831 10 10 and 2832 10 20. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of present investigation.
10. Sodium Hydrosulphite is widely used in diverse industrial sectors like Textiles, Soap, Molasses, Glue and reducing agent, Disulphide of metal ions to metals, linkage in wool hair etc. Major applications of the subject goods in different segments are listed below:
  - i. Textile - For Dyeing of Vat and Indigo dyes and reduction clearing of Synthetic fabric for stripping of dyes.
  - ii. Bleaching Aid - Ground Wood Pulp, Soap, Sugar, Molasses, Glue Kaolin (Clay).
  - iii. Reducing Agent - Reduction of Metal ions to Metals, Disulphide linkage in wool hair, Nitrogen compounds.
  - iv. Pharmaceuticals - Chemical reaction, De-Coloring final product.
  - v. Polymer - Oxygen scavenging agent.
11. With regards to the claim that products produced using zinc process are different from the products produced using sodium formate process, which is used by the producers in China PR, the Authority notes that the domestic industry is producing products using both processes, zinc as well as sodium formate. Further, the domestic industry has provided evidence to show that the subject goods are produced through both processes in the subject countries as well. Thus, there are no differences in such production process employed by the domestic industry and producers in China PR. Further, in the past investigations as well, the Authority has noted that the goods produced by the domestic industry are like article to the goods imported from China PR and Korea RP.
12. With regards to the claim that the products produced using zinc process and sodium formate process cannot be used interchangeably, it is noted that despite the products being produced through different routes, both the products are used interchangeably by the end-users. The domestic industry has contended that most of the consumers interchangeably use goods produced from the two processes and only 5% of the consumers use zinc route product. They have further submitted that these consumers use zinc route product not because the other product cannot be used, but only because costs on account of the product is not so significant and these consumers believe that zinc route use would ensure stability in their production process. Remaining consumers are using formate route product only because it is cheaper than zinc route product.
13. The importer, Sandeep Organics Limited, has also claimed that while the product having purity of 85-88% is imported from China PR, product with assay value 90% is imported from Korea RP. The importer claimed that the purity of the product impacted the price, demand, supply and usage thereof. In response, the domestic industry has relied upon the import data to show that the purity of the product is not affecting the price as below.

Purity	Imports from China PR (MT)	Price (Rs. /MT)
85%	762	63,141
88%	4,328	61,607
90%	811	61,202

14. Further, the domestic industry has provided evidence to show that while it has produced the product under consideration with assay level of 88% and 84%, the supporters have produced the product with assay levels ranging from 70%-92%. The importer has not shown that the products of different assay values are not like articles.

15. With regard to packaging of the goods, the importer has claimed that the goods imported from the subject countries are packed in 50 kg packing, which is costlier. The domestic industry has also submitted that it is supplying the subject goods in packs of 50 kg. Therefore, there is no difference in the size of packing of the goods.
16. With regard to the availability of substitute in the form of Thiourea dioxide, it is noted that Thiourea dioxide is not used as a substitute by any of the downstream user industries in India due to its poor performance when compared with the product under consideration.
17. As regards the submission that the domestic industry is producing Hydros D and Leucosafe D7, it is noted that these are only two variants of the product under consideration and both of these are comparable in terms of chemical composition and characteristics.
18. With regard to the request for exclusion of Grade E, it is noted that no credible evidence has been furnished by the opposing interested parties to establish that the demand exists for Grade E and that the domestic industry does not have the capability to manufacture the same.
19. With regard to the form of the product under consideration, the Authority notes that, as per the information on record, the subject goods are sold in powder form only.
20. The Authority further notes that, contrary to the contention of the importer, the goods produced by the domestic industry are BIS certified. The domestic industry has also provided a copy of its BIS Certificate.
21. It is thus noted that the goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. Therefore, the Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported goods.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **D.1. Submissions of the other interested parties**

22. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing.
  - i. Gulshan Chemicals does not produce subject goods with 90% purity as per their website.
  - ii. Kutch Chemical Industries Limited has neither mentioned production of the subject goods on their website, nor have they participated in the investigation.
  - iii. Other domestic producers have not submitted their data and thus the investigation based on the data of only one company is unfair.

##### **D.2. Submissions of the domestic industry**

23. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of domestic industry and standing.
  - i. The application has been filed by Transpek-Silox Industries Private Limited which is the single largest producer of the subject goods in the country and constitutes a major proportion of the total production in the country.
  - ii. The applicant has not imported the subject goods and are not related to any exporter or importer of the subject goods in India.
  - iii. The petition has been supported by Demosha Chemicals Private Limited, TCP Limited and Gulshan Chemicals Limited.
  - iv. Kutch Chemical Industries Limited has set up manufacturing facilities for the production of the product under consideration but has not commenced commercial production so far.
  - v. The applicant along with the supporters represent the entirety of the Indian industry.
  - vi. As Kutch Chemical Industries Limited have not commenced commercial production of the product under consideration, they are not a domestic producer of the subject goods and hence have not participated in the investigation.
  - vii. The production of the applicant constitutes a major proportion of the total domestic production and hence it constitutes domestic industry as affirmed by the Authority during the initiation. Non submission of data by the other domestic producers cannot prejudice the rights of the applicant in the present investigation.

**D.3. Examination by the Authority**

24. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

25. The application has been filed by Transpek-Silox Industry Private Limited. The applicant producer is not related to any importer or exporter of the subject goods in the subject countries, nor have they imported subject goods from the subject countries.

26. There are 3 other producers who are engaged in the manufacturing of the subject goods in India. All three producers of the subject goods have supported the present application, namely:

a. Demosha Chemicals Private Limited

b. TCP Limited

c. Gulshan Chemicals Limited

Another producer, Kutch Chemical Industries is in the process of setting up a plant for production of the subject goods.

27. The total domestic production has been determined on the basis of the details provided by the applicant. The applicant producer accounts for \*\*\*% of the total domestic production. Further, the applicant producer and supporters collectively account for 100% of the domestic production. The Authority therefore holds that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**E. CONFIDENTIALITY****E.1. Submissions of the other interested parties**

28. The other interested parties have submitted the following with regard to confidentiality. The domestic industry has not disclosed its distribution channel and whether they offer any commission to agents forming part of such channel. Such agents have also not filed any questionnaire.

**E.2. Submissions of the domestic industry**

29. Following submissions have been made by the domestic industry regarding confidentiality:

- i. Contrary to the contention of the interested parties, the domestic industry has disclosed that it has paid commission. Data regarding distribution channel or agents forming part of such channel was not required under the application proforma to the Authority.

**E.3. Examination by the Authority**

30. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*



31. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of their submissions with each other through e-mails.

## **F. MISCELLANEOUS ISSUES**

### **F.1. Submissions of the other interested parties**

32. Following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- i. Imposition of anti-dumping duties will create a monopolistic market in the country and the investigation is a clear case of anti-competition and trade restrictive practices by the domestic industry.
  - ii. Imposition of anti-dumping duty will lead to increase in prices of the subject goods in India.
  - iii. In the absence of imports, the domestic industry will not be able to cater to the demand of sugar, textile and paper industry.
  - iv. Majority of exporters mentioned in the petition have not exported the product under consideration into India during the period of investigation.
  - v. The domestic industry has not provided details regarding seasonal and geographical demand of the subject goods. Accordingly, the period of investigation should be determined as 2 years instead of 1 year, since the product may fail in one season.
  - vi. The product under consideration is hazardous and highly combustible when it comes in contact with water, as a result of which storage and transportation of the product is difficult, particularly in rainy season, reducing the demand during such period.
  - vii. The product under consideration is used mainly in textile/denim factories in Gujarat which have suffered due to COVID, many of which are either partly closed or have delayed payments.
  - viii. The product under consideration is used in sugar factories in North India and Maharashtra which have always been in a bad financial position.
  - ix. The domestic industry is receiving concessions and tax benefits from the Government.
  - x. The Authority has considered Sandeep Organics Private Limited as an interested party in the current investigation as well as in the investigation concerning Melamine and no documents have been asked till date in this regard.
  - xi. During the period of investigation, the company has purchased \*\*\* kg of subject goods worth Rs. \*\*\*.
  - xii. The domestic industry has not provided the details of costs and effects of change in location of its plant.
  - xiii. Essec Group is not a producer of the product under consideration
  - xiv. Sodium Sulphite, Sodium Sulfate, Sodium Thiosulfate are also raw materials for production through zinc process as per the website of the applicant, but the same has not been disclosed in the petition.
  - xv. The domestic industry offers three by-products, namely sodium formate, sodium sulphite and sodium thiosulphate, known as 'trisalts'.
  - xvi. Silox S.A and Silox Belgium, which are group companies of the applicant export the product under consideration worldwide but do not export to India.
  - xvii. Various holding companies of the applicant, namely Silox Holding, Silox UK, Silox Engis, Silox SA, Silox Belgium, HTCI, Shroff Group, Prayon, Cybelle, OCP & SRIW have not filed any information with the Authority.
  - xviii. The domestic industry has not submitted the certificate of analysis in their non-confidential petition.

### **F.2. Submissions of the domestic industry**

33. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
- i. Sandeep Organics Limited cannot be treated as an interested party since the company failed to file an importer's questionnaire response required by the Authority, in line with the decision of CESTAT in Merino Panels Products Limited vs Designated Authority and Automated Tyres Importers' Association

- of India vs Designated Authority. Further, as per the financial statements of Sandeep Organics Limited for 2017-18 to 2019-20, the company has made zero imports.
- ii. There is no demand-supply gap supply in the country as the domestic industry has sufficient capacity to cater to the entire demand in the country.
  - iii. In the absence of participation of consumers and the participation of only a party who failed to file the importer's questionnaire response, there is no evidence of any adverse impact on the consumers.
  - iv. The product under consideration is not a raw material but a mere chemical or additive for the consumers forming only a limited share in the cost of production and thus, imposition of duty would not result in the increase in costs for downstream users
  - v. There exists a healthy market situation in the country with significant inter-se competition between the domestic producers, offering the consumers ample choices.
  - vi. The increase in imports of the product under consideration from non-subject countries during the period when duties were imposed on China, indicates the willingness of the third countries to supply material to India in fair market conditions.
  - vii. Imposition of duties would help in conservation of outgoing foreign exchange.
  - viii. The domestic industry is competing with Chinese producers whose costs and prices are severely distorted by government intervention, which is evident from the fact that there is no claim of market economy treatment.
  - ix. The product under consideration forms only a minimal part of the cost of production in the textile industry that is, 0.02% of the total cost of production of denim and thus, a slight increase in the price shall not adversely impact the producers.
  - x. Contrary to the contention by the interested parties, the product under consideration is not used in the sugar industry.
  - xi. Even though the subject goods from Germany, China PR and Korea RP have been subject to anti-dumping duties in the past, there has been a significant increase in volume of subject imports when the duties expired in 2017. The anti-dumping duties are required as long as injurious dumping by foreign producers continue.
  - xii. Since the initiation notification was sent to the Embassy of the subject countries, it cannot be considered that the exporters were unaware of the investigation.
  - xiii. In response to the claim of the interested parties that the domestic industry benefitted from tax benefits or concession from the Government, it is submitted that no such benefits were received.
  - xiv. Contrary to the contention of the interested parties, the demand for the subject goods increased during the period of investigation.
  - xv. Contrary to claim of the interested parties, Esseco Group is a major producer of the subject goods with production units in Italy, United Kingdom and Brazil.
  - xvi. Silox S.A and Silox Belgium do not sell in the Indian market. Further, since the domestic industry itself is having under-utilized capacity, it makes no sense for these entities to export to India.
  - xvii. The group companies of the applicant-Silox Holding, Silox UK, Silox Engis, Silox SA, Silox Belgium, HTCI, Shroff Group, Prayon, Cybelle, OCP & SRIW do not fall within the scope of interested party as they are neither located in the subject countries nor are they exporters of the subject goods to India.
  - xviii. The certificate of analysis was not submitted with the petition merely because it is not required as per the application proforma. However, the domestic industry is willing to provide any further information that the Authority may require.
  - xix. The domestic industry has provided all details regarding costs and effects of change in location of its plant as part of the data submitted with the Authority.

### **F.3. Examination by the Authority**

34. With regards to the argument that the imposition of duties is likely to create a monopoly in the market, the Authority notes that at present there are four producers of the subject goods in the country. Hence, there does not seem any possibility of creation of a monopolistic market in the country. It is further noted that anti-dumping duty does not restrict imports, but only ensures that the imports enter the market at fair prices.

35. With regards to the claim of the other interested parties that the majority of exporters have not exported the subject goods during the period of investigation, the Authority notes that the notice of initiation was published in the Gazette of India and on the website of the DGTR. Further, the Authority had duly intimated the Embassy of the subject countries with regard to the initiation of the investigation. Despite that, none of the exporters from the subject countries have submitted questionnaire responses or participated in the present investigation.
36. The importer has also contended that the demand of the subject goods is seasonal and reduces in the rainy season. The Authority notes that the injury period consists of four financial years. Therefore, if the demand is affected by monsoon, it would be the case in each of the years. Therefore, the Authority does not find any merit in the submission to extend POI to a period of two years. Even otherwise, the Rules permit POI to be kept for a maximum of 18 months.
37. With regard to the contention of the domestic industry regarding failure of Sandeep Organic Private Limited to file a questionnaire response, the Authority notes that Trade Notice 11/2018 allows an interested party to participate in the investigation even without filing a response to the questionnaire. Therefore, even though the importer has not filed a response, the Authority has treated Sandeep Organic Private Limited as an interested party in the present investigation.
38. With regard to the contention that the imposition of anti-dumping duty will lead to an increase in prices of the subject goods in India, it is noted that the product under consideration is not a raw material, but merely a chemical or an additive and is used only for dyeing, bleaching, or as a reducing agent/oxygen scavenging agent, or for de-colouring and does not form a major part of the cost of production for the downstream users. Therefore, the imposition of duties would not result in a significant cost increase for the users. The Authority also notes that none of the users have participated in the investigation to provide any evidence of the adverse impact.

#### **G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

39. As per Section 9A (1) (c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

#### **G.1. Submissions of the domestic industry**

40. The domestic industry has submitted as follows with regards to normal value, export price and dumping margin.
  - i. Since no producer / exporter from China PR has participated to demonstrate that they are operating under market economy conditions, the normal value should be determined on the basis of provisions of para 7 of Annexure – I.
  - ii. Normal value for producers / exporters in China PR should be determined based on the prices of exports from European Union to India as imports from European Union constitute the largest share of imports after the subject countries, such imports are competing with the Chinese imports and such imports are not dumped. Thus, European Union is an appropriate surrogate country as per the principles laid down in Kuitun Jinjian Chemical Industry Co Limited v. Union of India.
  - iii. Normal value determined based on the cost of production in India despite availability of export price to third countries is inconsistent with Section 9A (1) (c) of the Anti-dumping Rules.

- iv. The Authority must determine normal value for producers / exporters in Korea RP based on the price of exports to third country which are in ordinary course of trade. If the export prices are above the cost of production of Korean producers determined by the Authority at the time of initiation, such sales should be considered as sales in ordinary course of trade and must be used to determine the normal value.
- v. The USDOC applies five percent test, whether exports are of like products and whether volume of sales is larger than the volume of sales to other countries, to determine the appropriate third country. Since volume of exports to Japan is more than the volume of exports to other countries, Japan may be considered as an appropriate third country and normal value may be determined based on price of exports from Korea RP to Japan.
- vi. If the Authority determines the normal value for producers / exporters in China PR and Korea RP based on the cost of production in India, actual cost of production should be considered and not the optimum cost of production. Adoption of optimum cost of production rewards the exporters for their non-participation in the present investigation.
- vii. Export price has been determined based on the CIF price which has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight to arrive at the ex-factory level.
- viii. Dumping margin for the subject countries is positive and significant.

## **G.2. Submissions of other interested parties**

- 41. No submissions have been made by other interested parties with regards to normal value, export price and dumping margin.

## **G.3. Examination by the Authority**

- 42. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

- 43. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. None of the producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the questionnaire response.

### **G.3.1. Determination of normal value**

#### **Normal value for China PR**

- 44. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under*

*investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

45. It is noted that while the provisions of Article 15 (a) (ii) have expired with effect on 11.12.2016, the provision under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. It is noted that no producers/ exporters from China PR has filed supplementary questionnaire response. Accordingly, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules. The normal value and export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.
46. As none of the producers / exporters from China PR have filed the questionnaire response in the present investigation, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

47. At the application stage, the applicant had claimed European Union as the surrogate country for China PR. The applicant claimed that the product under consideration is majorly produced and exported from three regions, China PR, Korea RP and the European Union. Since China PR and Korea RP are already subject of the present application, the applicant claimed that European Union is an appropriate market economy country. Accordingly, the applicant claimed normal value for China PR on the basis of price prevailing in European Union. However, during the course of the investigation, the applicant has also provided normal value on the basis of price of exports from European Union to India.

48. It is noted that as per the hierarchy given in law, the normal value should first be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price of exports from such country to other countries, including India. Where the normal value is determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, the market economy third country is required to be determined having regard to the level of development of the country concerned and the product in question. In the present case, while the applicant has provided information with regard to prices prevailing in European Union, it has failed to establish that the level of development in European Union is comparable to that of China PR. Accordingly, in the absence of any information with regard to comparability of level of development of European Union and China PR, the normal value cannot be determined on the basis of prices prevailing in European Union.
49. The applicant has also claimed normal value on the basis of export price of subject goods from European Union to India. In this regard, the Authority notes the findings of the Hon'ble CESTAT in the case of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India, wherein it was held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country to India, the relevant criteria for determining appropriate market economy third country is volume of exports from such country and that the country should not be dumping during the period of investigation. The Authority notes that there are significant imports from European Union, that is in excess of *de minimis*. Further, the imports from European Union cannot be considered as dumped. Accordingly, the Authority finds it appropriate to determine the normal value based on the export price of PUC from European Union to rest of the world.
50. For this purpose, the Authority has considered the WTA data for exports from European Union to the rest of the world. Since these prices are at FOB level, the price has been adjusted for commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available to arrive at the ex-factory price. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

#### **Normal value for Korea RP**

51. None of the producers / exporters from Korea RP have participated in the investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. In this regard, no information is available with regard to domestic selling price of the producers in Korea RP. The applicant has provided information with regard to price of exports from Korea RP to third countries. Further, the applicant has requested that ordinary course of trade test be applied to the exports from Korea RP. The Authority has determined the cost of production of the producers in Korea RP based on facts available, considering the cost of production of the domestic industry, having regard to best utilization of raw materials, utilities and production capacities. This cost of production has been compared to the export price from Korea RP to determine whether the exports have been made in the ordinary course of trade.
52. Further, the Authority has considered whether the volume of profitable exports is sufficient in volume, that is, whether it exceeds at least 5% of the volume of exports to India. Having applied the ordinary course of trade test and sufficiency test, the Authority finds that exports to Japan, Vietnam, Indonesia and USA can be considered for the determination of normal value. Since the volume of exports to Japan is the highest amongst these countries, the Authority finds it proper to consider it as the appropriate third country for determination of normal value. The export price from Korea RP to Japan has further been adjusted for commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available to arrive at the ex-factory price. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

#### **G.3.2. Determination of export price**

##### **Export price for China PR**

53. None of the producers / exporters from China PR have participated in the investigation. Accordingly, the export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, CIF price as per transaction-wise DGCI&S import data has been considered, which has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available.

##### **Export price for Korea RP**

54. None of the producers / exporters from Korea RP have participated in the investigation. Accordingly, the export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, CIF price as per transaction-wise DGCI&S import data has been considered, which has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available.

#### **G.3.3. Determination of dumping margin**

55. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined as follows:

SN	Countries	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
1	China PR	***	***	***	***	70-80
2	Korea RP	***	***	***	***	60-70

## H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

### H.1. Submissions of the domestic industry

56. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link.

- i. The applicant has shifted its plant from Atladra to Ekalbara during the injury period, as the former area had been declared as residential by the Government. The new plant was commissioned in the last week of February, 2017 and it produces the subject goods through the zinc route.
- ii. Injury to the domestic industry should be examined taking into account the effect of expiry of duties imposed on imports from China PR which expired in 2017 and on imports from Korea RP and Germany which expired in 2014, post which the volume of imports increased significantly and the performance of the domestic industry deteriorated.
- iii. The volume of imports from the subject countries has increased by 667% compared to the base year and imports from China PR alone have increased by 145 times over the injury period.
- iv. The volume of imports in relation to production and consumption have also increased significantly, by 654% and 613% respectively.
- v. The rate of increase in imports is much higher than increase in demand. While the demand increased by 7%, the volume of imports increased by 667%.
- vi. The volume of imports is entirely unnecessary as there is no demand-supply gap and the domestic industry is self-sufficient.
- vii. The landed price of the subject goods increased till 2018-19 but declined by 20% during the period of investigation and was the lowest over the injury period, resulting in unfair competition in the domestic market. Further, while the prices from the subject countries declined, the import prices from non-subject countries increased.
- viii. The imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry despite the domestic industry selling the subject goods below cost.
- ix. While both the cost of sales and selling price of the domestic industry increased till 2018-19, both declined in the period of investigation. However, the decline in selling prices was higher than the decline in the cost of sales. Further, the domestic industry was unable to increase its prices in tandem with the cost and was forced to compromise their prices due to decline in landed price.
- x. The domestic industry increased its capacity in 2017-18 as a result of which their fixed costs increased but the cost increase was not passed on to the consumers.
- xi. While the installed capacity increased in the period of investigation, the production and capacity utilization declined in the period of investigation.
- xii. The domestic sales of the domestic industry increased by only 4% over the period while the demand increased in 7%.
- xiii. The market share of the domestic industry and the Indian industry declined in the period of investigation while that of imports increased exponentially.
- xiv. The inventories increased in the period of investigation.
- xv. The profitability of the domestic industry declined by more than 300% resulting in significant losses, cash losses, and negative return on investment.
- xvi. The domestic industry recorded negative growth in its price parameters and its volume parameters, except capacity.

- xvii. The subject imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment as the domestic industry's profit before interest is negative.
- xviii. The domestic industry has not suffered injury due to any other factors.
- xix. There exists a causal link between the dumping and the injury to the domestic industry.
- xx. The revenue and profitability of other domestic producers have also declined over the injury period.
- xxi. Regarding the contention that the imports from Korea RP are not injurious, it was submitted that the imports from Korea RP account for more than 3% of total imports into the country and priced below the domestic selling price and non-injurious price of the domestic industry.
- xxii. In response to the claim that factories in China PR have shut down, it was submitted that the imports from China have shown significant increase regardless of such shutdown. Further, the shutdown was limited to Yichang, Hubei Province and there was no shutdown in other parts of China. Moreover, Guangdi Chemicals, the largest producer of the subject good had added capacity that was expected to become operational by 2019.
- xxiii. Contrary to the claim of the interested parties, the price of exports from the subject countries are lower than the price of exports from India to third countries. Export price of the domestic industry was lower than the domestic selling price till 2018-19 due to competition with exports from China PR and Korea RP in the international market. However, during the period of investigation, severe dumping resulted in lower domestic price than that of exports by the domestic industry.
- xxiv. The injury to the applicant is not on account of its inherent inefficient pricing policies as claimed by the interested parties, as the financial performance of the applicants improved and later declined with the cessation of duties on imports from China PR and significant increase in volume of dumped imports.
- xxv. Contrary to the contention of the interested parties, there are no imports from Japan during the period of investigation; hence injury cannot be attributed to exports from Japan.
- xxvi. Regarding the contention that the domestic industry is using old machinery, it is submitted that the domestic industry has constantly upgraded its technology and recently sourced Sulphur dioxide technology. In any case, injury to the domestic industry is required to be seen as it exists.
- xxvii. Prices of the product under consideration in the domestic industry are determined on ex-works basis and are not influenced by freight charges involved.

## **H.2. Submissions of the other interested parties**

- 57. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and causal link.
  - i. The domestic industry is suffering due to different pricing policy for different states of the country depending on the seasonal demand of the product in a particular region.
  - ii. The domestic industry provides the product at different prices to an end-user and a trader.
  - iii. The domestic industry is suffering since it is old and is using obsolete technology and machines.
  - iv. Imports from Korea RP are costly and the supply is irregular and less.
  - v. A number of factories in China PR have shut down due to high cost and excessive pollution.
  - vi. Exports by the domestic industry to other countries including USA and Turkey must be considered, which are high in number, implying that China PR and Korea RP are costlier than India. Further, exports are being made from Tuticorin but not from Vadodara.
  - vii. Exports by BASF, Brüggemann and from Japan must be investigated to ascertain whether injury to the domestic industry can be attributed to such imports.
  - viii. Since the plant of the domestic industry is located in Vadodara, the consumers in other parts of India are charged extra due to additional transportation.
  - ix. The domestic industry has expanded their production capacity from 4600 tonnes to 14800 tonnes per year, by adding filter dryers and other balancing equipment, and due to consistent R&D effort, they were able to increase yield per batch of the product, while achieving higher production.

## **H.3. Examination by the Authority**

- 58. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.



**I. Cumulative assessment**

59. Article 3.3 of the WTO Agreement and Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
  - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
60. The Authority notes that:
- The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
  - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
  - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
61. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR and Korea RP.
62. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
63. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and the other interested party on injury to the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority here under ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

**II. Assessment of demand / Apparent consumption**

64. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	103	104
Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	98	96
Subject imports	MT	853	1,376	4,656	6,540
Other imports	MT	2,374	1,568	450	418
Total demand	MT	46,608	46,402	48,389	50,094

65. It is noted that the demand for the product under consideration declined marginally in 2017-18 but has increased thereafter and in the period of investigation.

### III. Volume effect of dumped imports

66. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject imports	MT	853	1,376	4,656	6,540
China PR	MT	43	710	4,080	6,288
Korea RP	MT	810	666	576	252
Other imports	MT	2,374	1,568	450	418
Subject Imports in relation to					
Domestic production	%	1.60%	2.36%	8.11%	12.03%
Consumption	%	1.83%	2.97%	9.62%	13.05%
Total Imports	%	26.43%	46.75%	91.19%	93.99%

67. It is noted that:

- The volume of subject imports increased significantly throughout the injury period and was the highest during the period of investigation. Over the period, the imports have increased by 667%.
- The volume of subject imports also increased significantly in relation to the domestic production and consumption.
- The share of subject imports in total imports also increased drastically, to more than 90% in the period of investigation, while imports from other countries have declined and were marginal during the period of investigation.

### IV. Price effect of the dumped imports

68. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject countries with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

#### a. Price undercutting

69. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
China PR					
Net selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	126	105
Landed price	₹/MT	52,354	89,875	83,229	66,889
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***

Price undercutting	Range	45-55	(0-10)	10-20	20-30
Korea RP					
Net selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	126	105
Landed price	₹/MT	68,646	68,693	86,634	76,938
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	20-30	10-20	0-10
Subject countries					
Net selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	126	105
Landed price	₹/MT	67,825	79,626	83,650	67,276
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	0-10	10-20	20-30

70. It is noted that the subject imports are entering the market at a price significantly below the selling price of the domestic industry and are undercutting the prices of the domestic industry

**b. Price suppression / depression**

71. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	116	126	123
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	111	126	105
Landed Price from subject country	Rs/MT	67,825	79,626	83,650	67,276
Trend		100	117	123	99

72. It is seen that both cost of sales and selling price of the domestic industry have increased over the injury period. However, the increase in cost of sales was at a much higher rate than increase in the selling price. By comparison, the landed price of imports has declined over the period. Hence, the subject imports have suppressed the prices of the domestic industry.

**V. Economic parameters of the domestic industry**

73. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

**a. Capacity, production, capacity utilization and sale**

74. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	145	105	127
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	114	111
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	108	88
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	103	104

75. It is seen that:

- The capacity of the domestic industry declined in 2018-19 but has increased during the period of investigation due to capacity expansion by the domestic producer.
- The production of the domestic industry increased in 2017-18 but has declined thereafter in 2018-19 and in the period of investigation. Despite increase in capacity during the period of investigation, the production of the domestic industry has shown a decline.
- The capacity utilization of the domestic industry increased in 2018-19 due to decline in capacity. However, the capacity utilization has reduced again during the period of investigation.
- The domestic sales of the domestic industry declined in 2018-19 but increased marginally during the period of investigation.

**b. Market share**

76. Market share of the domestic industry and other Indian producers is as below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	99	97
Supporters	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	94	89
Subject imports	%	1.83%	2.97%	9.62%	13.05%
Other imports	%	5.09%	3.38%	0.93%	0.83%

77. It is noted that the market share of subject imports increased substantially over the injury period, while share of other imports declined. As against this, the market share of the domestic industry increased till 2017-18 but thereafter declined. Further, the market share of the Indian industry as whole also declined during the period of investigation.

**c. Inventories**

78. Inventories with the domestic industry over the injury period are as below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	69	117

79. It is noted that the inventories of the domestic industry declined in 2017-18 but increased significantly in the period of investigation.

**d. Profitability, cash profits and return on capital employed**

80. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>116</i>	<i>126</i>	<i>123</i>
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>126</i>	<i>105</i>
Profit before tax	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>17</i>	<i>126</i>	<i>(233)</i>
Total Profit before Tax	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>18</i>	<i>129</i>	<i>(243)</i>
Total Profit before interest and taxes	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>22</i>	<i>128</i>	<i>(228)</i>
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>160</i>	<i>(81)</i>
Return on capital employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>77</i>	<i>(115)</i>

81. It is seen that:

- The profits of the domestic industry increased in 2018-19 but deteriorated in the period of investigation. The domestic industry suffered significant losses during the period of investigation.
- The cash profits of the domestic industry increased till 2018-19, but the domestic industry suffered cash losses in the period of investigation.
- The return on capital employed of the domestic industry also declined and was negative in the period of investigation.

**e. Employment, wages and productivity**

82. Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
No. of employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>107</i>	<i>94</i>
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>114</i>	<i>111</i>
Productivity per employee	MT/Employee	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>119</i>
Wages per unit	₹ lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>88</i>	<i>84</i>	<i>101</i>

83. It is seen that the number of employees of the domestic industry increased in 2017-18 but declined thereafter, while wages increased. Further, productivity of the domestic industry has improved over the period.

**f. Growth**

84. The trend of volume and profit parameters of the domestic industry are as under:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	-	17%	-3%	-2%
Domestic sales	%	-	8%	-5%	2%
Profits	%	-	-62%	292%	-265%
Cash profits	%	-	12%	57%	-148%
Return on capital employed	%	-	-78%	300%	-220%

85. It is noted that the performance of the domestic industry has deteriorated during the period of investigation. While the production of the domestic industry has shown negative growth, the sales of the domestic industry have marginally grown during the period of investigation when compared to the previous year. Further, the profitability parameters have shown significant negative growth in the period of investigation.

**g. Ability to raise capital investment**

86. The Authority notes that the domestic industry is incurring significant losses and suffering negative return on its capital employed. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investment has clearly adversely affected by the subject imports.

**h. Factors affecting prices**

87. It is noted that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the domestic industry has not been able to increase its prices in line with the increase in its cost of sales, due to the decline in landed price. Therefore, it can be concluded that the subject imports have adversely impacted the prices of the domestic industry.

**i. Magnitude of dumping**

88. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

**I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

89. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilization of the raw materials, utilities and capacities by the domestic industry over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
90. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

**INJURY MARGIN TABLE**

SN	Countries	NIP	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(Rs/MT)	(Rs/MT)	(Rs/MT)	(%)	(Range)
1	China PR	***	66,889	***	***	30-40
2	Korea RP	***	76,938	***	***	20-30

**J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

91. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

**a. Volume and prices of imports from third countries**

92. It is noted that other than imports from the subject countries, there are significant imports from European Union. However, such imports are priced much higher than the price of imports from the subject countries as well as the prices of the domestic industry. Other than European Union, there are only imports from Hong Kong, which are negligible in volume. Therefore, the imports from these countries are not causing injury to the domestic industry.

**b. Contraction in demand**

93. It is noted that the demand of the subject goods has increased in the period of investigation. Therefore, possible contraction in demand cannot cause injury to the domestic industry.

**c. Changes in the pattern of consumption**

94. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

**d. Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers**

95. The Authority notes that there are no trade restrictive practices or conditions of competition between the foreign and domestic producers brought to the notice of the Authority by any interested party, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**e. Developments in technology**

96. The Authority notes that there has been no material change in technology for production of the product to which the injury suffered by the domestic industry can be attributed.

**f. Export performance**

97. The Authority has considered data for the domestic operations only for injury assessment. Hence, any possible deterioration in the export performance of the domestic industry cannot be a cause for the injury to the domestic industry.

**g. Productivity**

98. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has declined only due to decline in production and thus, injury to the domestic industry is not on this account.

**h. Performance of other products of the company**

99. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

**Conclusions on injury and causal link**

100. The Authority notes the following –

- i. There is significant dumping of the subject goods in India, resulting in increased demand for dumped imports.
- ii. The volume of dumped imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- iii. While the market share of the subject imports has increased, the domestic industry has lost its market share.
- iv. As a result, the production and capacity utilization of the domestic industry have declined in the period of investigation.
- v. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.

- vi. The imports have forced the domestic to sell its goods at reduced prices and have suppressed the prices of the domestic industry.
- vii. The domestic industry has suffered losses, cash losses and negative returns on capital employed.
- viii. The profitability parameters of the domestic industry have shown a negative growth in the period of investigation.

## **K. POST DISCLOSURE COMMENTS**

### **K.1 Submissions of the other interested parties**

101. The other interested parties have reiterated their submissions with regard to scope of product under consideration, and impact of duty. Additionally, it has been submitted that the product has been subject to duties since several years.

### **K.2 Submissions of the domestic industry**

102. The domestic industry has submitted as follows in its comments to the disclosure statement.
- a. The essential facts concerning injury and causal link which shall form the basis of the decision have not been disclosed.
  - b. As per Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement and as held in China - GOES (US), European Communities - Farmed Salmon (Norway) and by High Court in Nirma Limited Vs. Union of India, the disclosure statement should contain the conclusions of the designated authority on those essential facts which would form the basis for its decision as to whether or not to apply definitive measures. Therefore, the facts with regard to dumping, injury and causal link are required to be disclosed. This is paramount for ensuring the ability of the interested parties to defend their interests.
  - c. The producers in the subject countries have continued dumping despite long duration of duties indicating that such behaviour is not temporary.
  - d. The producers in China PR have an estimated capacity of 1.29 million MT which far exceeds the global demand of 0.5 million MT, leading to stiff competition for a limited demand.
  - e. There is no demand-supply gap supply as the domestic industry has sufficient capacity to cater to the entire demand in the country. Further, despite sufficient demand, the domestic industry was forced to operate underutilized capacities.
  - f. There exists a healthy market situation in the country with significant inter-se competition between the domestic producers, offering the consumers ample choices.
  - g. The domestic industry has been producing the subject goods for more than twenty-five years and has been trying to improve cost competitiveness based on market demands.
  - h. The producers in the subject countries are selectively selling the subject goods in India at prices which are below the prevailing prices in global markets as well as below the prices at which they themselves sell to other countries.
  - i. India is the second largest market for the producers in China PR.
  - j. The domestic industry is competing with Chinese producers whose costs and prices are severely distorted by government intervention, and thus, imposition of duties will offset such trade distortion.
  - k. The dumped goods have caused severe injury to the domestic industry and the imposition of duties would help in reviving the domestic industry providing for employment generation.
  - l. The product under consideration is merely a chemical or additive for the consumers forming only a limited share in the cost of production.
  - m. The product under consideration is produced using only locally sourced raw materials and thus, the Indian industry provides a market to upstream raw material producers as well.
  - n. None of the foreign producers / exporters have participated in the present investigation indicating their lack of concern for the investigation.
  - o. In the absence of participation of consumers, there is no evidence of any adverse impact on the consumers. It is submitted that the impact of a duty @20% on various end use sectors would be 0.004% to 0.06%.



- p. The increase in product under consideration from non-subject countries during the period when duties were imposed on China, indicates the willingness of the third countries to supply material to India in fair market conditions.
- q. Imposition of duties would help in conservation of outgoing foreign exchange.

### **K.3 Examination by the Authority**

- 103. The Authority notes that some of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in the final findings. Further, the Authority has examined the additional submissions of the interested parties as under:
- 104. With respect to the submission of the interested parties regarding duration of duty, it is noted that in each of the past investigations, the Authority has found dumping, injury and causal link, or likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury. Even in the present case, the Authority has found significant dumping, causing injury to the domestic industry. Therefore, despite previous history of duties, the producers in the subject countries have continued dumping. In such a situation, anti-dumping duty needs to be imposed, irrespective of the period of duty.
- 105. With respect to the submission of the domestic industry that the disclosure statement has not disclosed the essential facts concerning whether there is injury and causal link, the Authority notes that only the essential facts are required to be disclosed in the disclosure statement and the same has been done.

### **L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**

- 106. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 107. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. It is noted that none of the users have participated in the investigation. However, the domestic industry has provided information with regard to impact of duty on downstream product. As per the information provided by the domestic industry, the impact of a duty of 20% on various end use sectors would be 0.004% to 0.06%.
- 108. The Authority notes that the product under consideration is being used as a chemical or additive, and not as a raw material and thus its cost constitutes only a small percentage of the cost of the downstream product. Therefore, the imposition of duties would not have an adverse impact on the prices of the downstream users.
- 109. It is further noted that the product under consideration has a history of dumping. Despite past history of duties, the dumping of the subject goods has not abated. The imports of subject goods from China PR were attracting duties till 2017. Once the duties expired, the foreign producers resumed dumping in the Indian market again. The Authority also notes that the evidence provided by the domestic industry shows that the price of subject imports is significantly lower than the prices at which the producers in the subject countries are supplying to other markets. As a result, India has emerged as a major export market for the producers in the subject countries, despite being self-sufficient in the product. Therefore, unless duties are imposed, the producers in the subject countries are going to continue injurious dumping.
- 110. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly when the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

### **M. CONCLUSION**

- 111. Having regard to the contentions raised, information received, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
  - i. The product under consideration has been exported from the subject countries at a price below the normal, resulting in dumping.

- ii. The volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- iii. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- iv. The imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- v. The production and capacity utilization of the domestic industry have declined during the period of investigation, despite capacity addition by the domestic industry.
- vi. The sales of the domestic industry have increased marginally during the period of investigation.
- vii. The market share of the domestic producers has declined, while that of imports has increased.
- viii. The inventories of the domestic industry have increased in the period of investigation.
- ix. The profitability of the domestic industry has shown a significant decline and the domestic industry has suffered losses, cash losses and negative returns on investment during the period of investigation.
- x. There is a causal link between the dumping of the product under consideration from the subject countries and injury to the domestic industry.
- xi. The injury margin determined in the present investigation is substantially lower than the dumping margin. Since the duty recommended is based on injury margin as per lesser duty rule, the duty recommended is fairly reasonable and it is not likely to cause any adverse impact on the downstream industry.

## N. RECOMMENDATIONS

112. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link thereof in terms of Rules and having established positive dumping margin as well material injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject countries, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
113. In view of above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the table below on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from China PR and Korea RP for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.
114. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

**DUTY TABLE**

SN	Tariff Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	China PR	Any country including China PR	Any	440	USD	MT
2	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	440	USD	MT
3	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	Korea RP	Any country including Korea RP	Any	300	USD	MT

4	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	Any country other than China PR and Korea RP	Korea RP	Any	300	USD	MT
---	------------------	-------------------------	---	----------	-----	-----	-----	----

**O. FURTHER PROCEDURE**

115. An appeal against the order for the Central Government that, may arise out of this recommendation shall lie in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority